

न्यायपुंज

स्मारिका



न्यायः मम धर्मः

SOUVENIR 2014, ADHIVAKTA PARISHAD, BIHAR

Editor

Kaushal Kumar Singh
Advocate



Sub Editor

Lakmesh Marvind
Advocate

Chetan Kumar
Advocate



Editorial Office

Gorakhnath Lane

Boring Road, Patna-800001 (Bihar)

E-mail : adhivaktaparishadbihar@gmail.com

Phone-0612-2535891



Design & Production

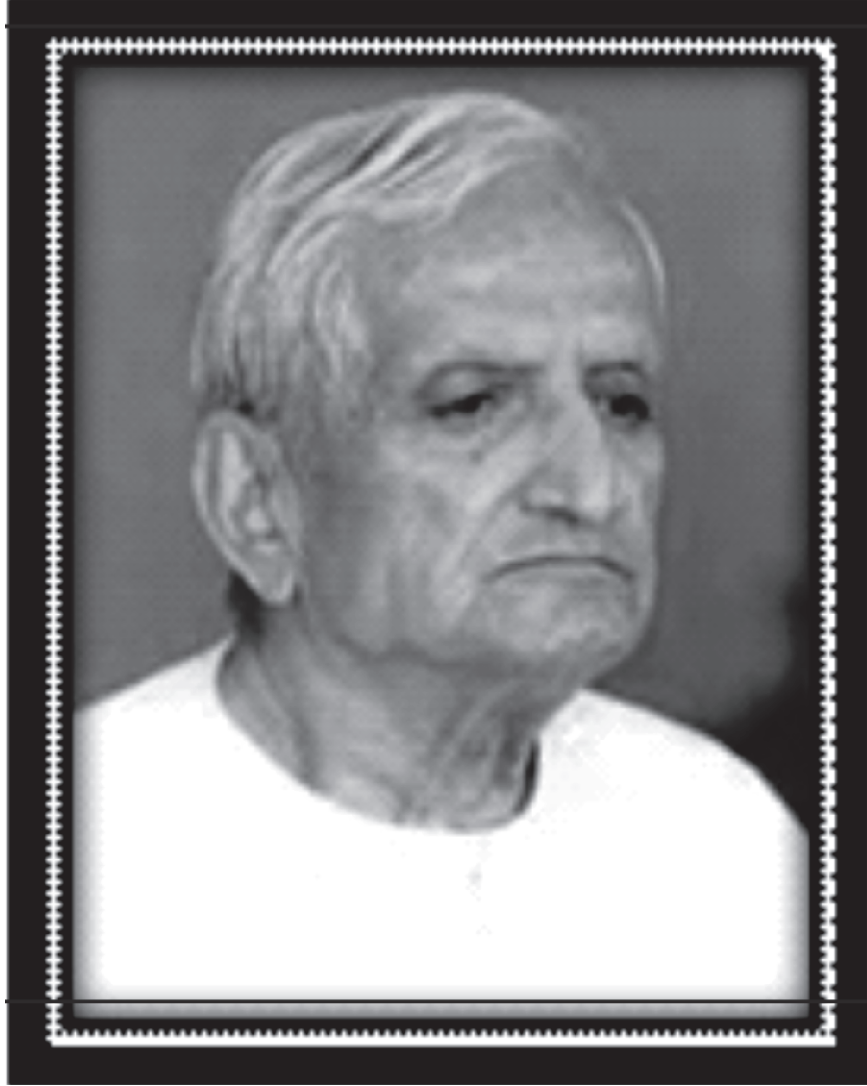
Tarang Press & Publications Pvt. Ltd.
Shivpuri, Patna-23

Disclaimer : Any Opinions or views on any contemporary or past topics, issues or developments expressed by third parties, whether in abstract or in interviews, are not necessarily shared by editor / publisher. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts and forums in Patna only.

INDEX

हमारे प्रेरणास्रोत	2
Reception Committee for National Council Meeting of Akhil Bhartiya Adhivakta Parishad	3
शुभकामना संदेश	5
सम्पादकीय	12
अधिवक्ता परिषद् बिहार-एक झलक - सुनील कुमार	14
Strengthening Justice Delivery System - Hon'ble Justice Ajay Kumar Tripathi	18
Good Legislations for farmers in bad hands of Executive - Ram Suresh Roy	22
Gair Majarua Aam & Gair Majarua Khas - Keshav Shrivastava	24
Demand of the Day - Rabindra Kumar Sinha	25
Temporary Provision of Article 370 of the Constitution of Bharat How Long to Exist? - Pramod Kumar Sinha	26
Consequences of Non-deduction, Non-deposit and Late Deposit of Tax Deducted at source - Shivnath Pd. Agrawal	29
The Ghost of Khas Mahal - Amar Sinha	31
Gram Panchayat Raj - Shri Prakash Shrivastava	34
The Hindu Marriage Act 1955 MARRIAGE A SACRAMENT - शिखा सिंह	37
Impact of Annual Information Return on common Tax Payer Assesses - R.K. Mishra	39
हमारे प्रेरणास्रोत दत्तोपंत ठेंगड़ी - राकेश चन्द्र वर्मा	41
भारत की शिक्षा नीति एवं अधिवक्ताओं की भूमिका - डा० प्रेमनाथ पाण्डेय	43
Erosion of Values in Judicial System and its Refurbishment - Lakmesh Marvind	45
अनैतिक मानव व्यापार प्रतिबंध कानून (ITPA) और इसकी चोट - शोभा चौबे	48

हमारे प्रेरणास्रोत



महामना स्व. दत्तोपंत ठेंगड़ी

आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः ।
असंगो निस्पृहः शान्तो भ्रमात्संसारवानिव ॥

आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित, संग रहित, इच्छा रहित और शांत है । मात्र भ्रम होने से यह संसारी जैसा भासता है ।

(अष्टाचक्र गीता)

Akhil Bhartiya Adhivakta Parishad National Council Meeting Patna RECEPTION COMMITTEE

Honble Justice S.N. Jha

Rtd. Chief Justice J & K, Rajasthan
& Former Chairman of Bihar Human Rights Commission

President

Sri Ram Suresh Rai

Senior Advocate, Patna High Court

Vice-President

Sri Srinandan Pd. Singh

Advocate, Patna High Court

Vice-President

Sri Shiv Kumar Pandey

Senior Advocate, Civil Court, Sasaram

Vice-President

Sri Subodh Kumar Sinha

Advocate, Patna High Court

Vice-President

Sri Santosh Chakhaiyar

Advocate, Civil Court, Patna

Vice-President

Smt. Ishrat Fatima

Advocate, Patna High Court

Vice-President

Sri Sanjay Kumar

Advocate, Assistant Solicitor General, Govt. of India
Patna High Court

General Secretary

Sri Deepak Kumar Gupta

Advocate, Secretary, B.A., City Court, Patna

Secretary

Dr. Binod Bihari Sinha

Advocate, Patna High Court

Secretary

Dr. Chandrashekhar Azad

Advocate, Patna High Court

Secretary

Dr. Shobha Chanbey

Advocate, Patna High Court

Secretary

Sri Prabhat Kumar Bhagat

Advocate, Civil Court, Jamui

Member

Sri Arvind Kumar Thakur

Advocate, President, D.B.A., Sitamarhi

Member

Sri Prabhunnath Singh

Advocate, Govt. Pleader, Civil Court, Buxar

Member

Sri Satyendra Kr. Jha

Advocate, Patna High Court

Member

Sri Harihar Nath Sharma

Advocate, Civil Court, Patna

Member

Km. Archana Singh

Advocate, Patna High Court

Member

Km. Manisha Singh

Advocate, Patna High Court

Member

Sri Ritesh Kumar Singh

Advocate, Patna High Court

Member

Sri Shankar Prasad Singh

Advocate, Civil Court, Patna

Member

**DR. D.Y. PATIL
GOVERNOR OF BIHAR**



**RAJ BHAVAN
PATNA-800 022**
Ph. 0612-2217626 Fax 2786184



24 अक्टूबर, 2014

संदेश

अधिवक्ता परिषद् पटना द्वारा 'न्यायपुंज' नामक स्मारिका के प्रकाशन का निर्णय स्वागतयोग्य है। सबको सहज-सुगम रूप से कम खर्च पर न्याय कैसे सुलभ कराया जाए-यह एक ज्वलंत समस्या है। हर तरह की कानूनी जानकारी और सुविधाएँ आम गरीबों तक सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके, ताकि वे अपने विकास और कल्याण के रास्ते ढूँढ़ पाएँ - यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है।

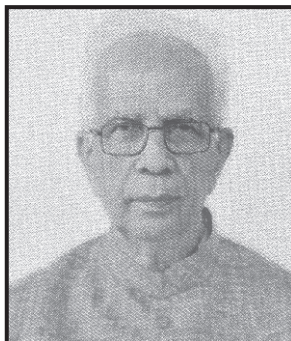
आशा है, 'स्मारिका' न्यायिक सन्दर्भों व मामलों से जुड़े विभिन्न विषयों पर केन्द्रित उपयोगी आलेखों से परिपूर्ण होगी। इसके सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करें।

२०/-
(डॉ० डी० वाई० पाटील)
राज्यपाल, बिहार

केशरी नाथ त्रिपाठी
राज्यपाल, पश्चिम बंगाल

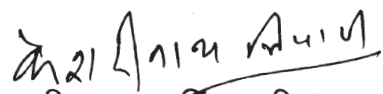


राजभवन
दार्जिलिंग



संदेश

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक दिनांक २७, २८ एवं २९ दिसम्बर, २०१४ को पटना में आयोजित हो रही है। इस अवसर पर "न्यायपुंज" नामक स्मारिका भी प्रकाशित की जाएगी। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकाशन में पाठकों के लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी जिससे समाज के हर वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। मैं इस प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ।


केशरी नाथ त्रिपाठी

२०.१०.२०१४



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

सरसंघचालक : मोहन म. भागवत ■ सरकार्यवाह : सुरेश (भय्या) स. जोशी

युगाब्द :

प्रधान कार्यालय : डा. हेडगेवार भवन, महाल, नागपूर-440 032

दूरभाष : 0712-2723003, 2720150, (2721589 फॅक्स)

email : hedgewarbhavan@rediffmail.com

पत्र क्र.-स्म/14/04

तिथि-युगाब्द 5116, भा.कृ.11

दिनांक-22-08-14

श्रीमान कौशल कुमार सिंह जी

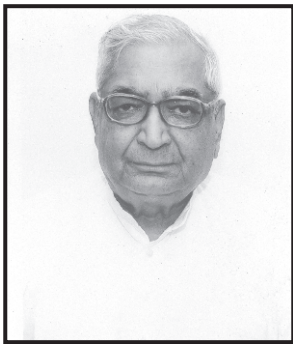
नमस्कार !

अत्यंत हर्ष की बात है कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् की राष्ट्रीय परिषद बैठक के अवसर पर 'न्यायपुंज' नामक स्मारिका का प्रकाशन हो रहा है ।

यह स्मारिका निश्चित ही पाठकों को उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने में सफल होगी ऐसा विश्वास है । इस प्रयास के लिए आयोजकों को साधुवाद और शुभेच्छा ।

आपका

(भय्या जोशी)



केशव कुंज,

झंडेवाला

नयी दिल्ली - ११००५५

संदेश

श्रीमान कौशल कुमार जी

अधिवक्ता

सम्पादक, न्यायपुञ्ज

आपके पत्र द्वारा जानकारी मिली इस वर्ष अधिवक्ता परिषद् की “अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ” की बैठक पटना, बिहार में होने

जा रही है।

अधिवक्ता परिषद् देश में भारतीय अस्मिता के अनुकूल संविधान और न्यायिक व्यवस्था स्थापित हो इसके लिए प्रयत्नशील है।

आपके यहाँ से इस अवसर पर “न्यायपुञ्ज” नामक स्मारिका का भी प्रकाशन होने जा रहा है स्मारिका एवं बैठक की सफलता की कामना करता हूँ।

आपका


सूर्यकृष्ण

अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद्

पंजीयन संख्या -39403/2001

कार्यालय:प्रवासी भवन, 50 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110002

बलदेव राज महाजन

दूरभाष : 09814003021

वरिष्ठ अधिवक्ता

0172-2770292, 2548801

राष्ट्रीय अध्यक्ष

email: baldevmahajan@rediffmail.com

3321, सैक्टर 19-डी,

चण्डीगढ़-160019

संदेश

परम बन्धु श्री कौशल कुमार सिंह जी,

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अधिवक्ता परिषद् बिहार, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् की पटना में हो रही राष्ट्रीय परिषद् बैठक, 2014 के अवसर पर “न्यायपुंज” नामक स्मारिका का प्रकाशन कर रही है, जो सराहनीय है।

अधिवक्ता समाज के जागृत एवम् सुशिक्षित महत्वपूर्ण अंग है जो सामाजिक व्यवस्था के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवम् व्यवस्थाओं का संरक्षण करते हैं।

स्मारिका पाठकों को योग्य मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएँ।

बलदेव राज महाजन

बलदेव राज महाजन
राष्ट्रीय अध्यक्ष



वीरेन्द्र मोहन भारद्वाज
अधिवक्ता
क्षेत्रीय मंत्री (बिहार, झारखण्ड)
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद्
नई दिल्ली।

मो0: +91 9810136319

दिनांक: 16.10.2014

संदेश

श्री कौशल कुमार सिंह
अधिवक्ता
संपादक
“न्यायपुंज” स्मारिका
अधिवक्ता परिषद्, बिहार
पटना, (बिहार)।

प्रिय बन्धु,

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय परिषद् की बैठक दिनांक 27, 28 एवं 29 दिसम्बर 2014 जो पटना (बिहार) में सम्पन्न होनी तय हुई है। इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद्, बिहार एक विशेष स्मारिका “न्यायपुंज” का प्रकाशन कर रही है। मेरा विश्वास है कि इससे कार्यकर्ताओं में संगठनात्मक विचार एवं विकास का संचार होगा तथा संगठन के अनुरूप कार्य का सुचारु रूप से विस्तार होगा। मैं मंगल कामना करता हूँ कि इस शुभ कार्य में पूर्णतया: सफलता मिलेगी।

शुभ कामनाओं सहित।

शुभेच्छु

वीरेन्द्र मोहन भारद्वाज
(वीरेन्द्र मोहन भारद्वाज)

: निबंधन संख्या : 51 / 1998-1999

E-mail : vbbihar@gmail.com

दूरभाष : 0612- 2665469

मोबाईल : +919431057577

विद्या भारती, बिहार

प्रेमकुंज, विन्ध्यवासिनी पथ, कदमकुआँ, पटना- 800003

पत्रांक : VBB/PAT/...9.5/11/14...

दिनांक : 10/11/2014

संदेश

यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् की राष्ट्रीय परिषद बैठक के अवसर पर “न्यायपुंज” नामक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

उक्त बैठक की सफलता एवं “न्यायपुंज” स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ तथा अधिवक्ता परिषद् बिहार के सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को इस अवसर पर बहुत-बहुत बधाई।

भवदीय

कमल किशोर सिन्हा
(कमल किशोर सिन्हा)
क्षेत्रीय मंत्री

अपनी बात, आपके साथ



कौशल कुमार सिंह
सम्पादक

कहाँ से आरंभ करें! भावनाओं का ज्वार!! उमड़ते-धुमड़ते कई विचारों का प्रवाह एक साथ सामने आने को आतुर है। बिहार की ऐतिहासिक पुण्य धरा के गौरवशाली अतीत की साक्षी पाटलिपुत्र की पावन गरिमामयी भूमि पर राष्ट्रीय परिषद्, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् की बैठक के आतिथ्य का रोमांचक और गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त कर हमें अतिशय आनंद और हर्ष की अनुभूति हो रही है। राजा जनक और माँ जानकी की धरती बिहार, गौतम बुद्ध, महावीर और महर्षि विश्वामित्र की तप, ज्ञान, कर्म भूमि बिहार का हृदय स्थल पुण्य सलिला भागीरथी के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र जो सम्राट अशोक के वैभवशाली मगध साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव के साथ-साथ श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जन्मस्थली होने का सौभाग्य समेटे भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के संघर्षपूर्ण दिनों में डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री जय प्रकाश नारायण, श्री योगेन्द्र शुक्ल एवं डा० सच्चिदानंद सिन्हा जैसे प्रखर प्रतिभाशाली राजनीतिक तपस्वियों की कर्मभूमि रहा है, उसी उर्जावान और जाग्रत नगरी में यह बैठक एक नए विचारपुंज एवं नवीन संकल्प के साथ नवोन्मेषित होकर अधिवक्ता परिषद् की सफलता को उच्च शिखर पर आसीन करने की ओर अग्रसर है। भारतवर्ष में अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा

यह संगठन एक स्थायी संविधान सभा के रूप में स्थापित होने के अपने गुरुतर लक्ष्य की ओर धीरे, गंभीर कदमों से बढ़ता हुआ पटना की ऐतिहासिक भूमि पर एक नए आयाम को स्पर्श करे हम सब इसी कामना के पथ पर गतिशील है।

न्याय मानव सभ्यता की आधारभूत आवश्यकता है। प्रागैतिहासिक काल में जब आदि मानव, हमारे पूर्वज पर्वत कंदराओं और वनों में विचरते थे उस समय जब किसी दुर्बल मानव के शिकार को कोई बलशाली बलात् छीन ले गया होगा तो हतप्रभ खड़े व्यथित मानव के मन में न्याय पाने की पहली इच्छा जाग्रत हुई होगी और कालांतर में कबीलाई संस्कृति से गुजरते हुए मानव ने विकास की लंबी यात्रा तय की है और तदनुरूप न्याय व्यवस्था का भी समुचित उन्नयन और विकास किया है और आज के कालखंड में भी उत्तरोत्तर इस पथ पर अग्रसर है क्योंकि मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठतम रचना है और बुद्धि, विवेक और ज्ञान द्वारा वह अपने समाज के अभ्युदय के लिए बेहतर न्याय मूल्यों और राज व्यवस्था के प्रति संघर्षरत रहता है और ऐसी अभ्युदित न्याय व्यवस्था के बिना मानव सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक सक्षम और सार्थक राज व्यवस्था का प्रथम कर्तव्य न्याय देना है।

संपूर्ण न्याय व्यवस्था और न्यायतन्त्र की वर्तमान संदर्भ में पुनरावलोकन की आवश्यकता बनी है। स्वच्छ और पारदर्शी न्यायतन्त्र वर्तमान समाज की जटिलताओं के बीच अपरिहार्य है। बड़ी श्रद्धा से सामान्य मानव समाज न्यायपालिका पर अपार आदर और विश्वास रखता है और वर्तमान में हिंसा, आर्थिक असमानता और शोषण के कारण मुकदमों का बड़ा भार इस तन्त्र पर है क्योंकि समाज में अपसंस्कृति बढ़ी है और आपसी प्रेस सौहार्द का वातावरण भी घटा है, फिर कार्यपालिका भी आश्वस्त नहीं करती। अतः तमाम जटिलताओं को दूर कर हमें सस्ता, सरल और सुलभ न्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का गुरुतर दायित्व वहन करने के लिए कृतसंकल्प होना होगा क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 40 हजार मुकदमों लंबित हैं और एक अनुमान के अनुसार 21 उच्च न्यायालयों में लगभग 30 लाख मामले विचाराधीन हैं। निचली अदालतों का यह आँकड़ा तो और भी डर पैदा करता है। वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालयों में करीब 300 पद और निचली अदालतों में लगभग 3300 न्यायकर्ताओं के पद रिक्त हैं और न्याय में विलंब अन्याय होता है।

देश में अनेक सुधारों का दौर चला रहा है। आर्थिक सुधारों की काफी बातें होती हैं, चुनाव सुधारों की भी बहस जारी है पर दुखद है कि न्यायिक सुधारों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अपने ही बोझ से डगमगाती न्यायपालिका संपूर्ण विपरीत परिस्थिति एवं सीमित संसाधनों में भी न्यायतन्त्र पर आम जनों का विश्वास और आस्था बनाए रखने के लिए संघर्षरत है क्योंकि न्याय और न्यायमूर्ति भारत की श्रद्धा हैं और अधिवक्तागण इस श्रद्धा के वाहक।

न्यायपालिका स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और इसकी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण बनाई गई है परंतु इसके उपरान्त भी भारतीय न्याय व्यवस्था कई संदर्भों में कई प्रश्नों के घेरे में है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की पारदर्शिता भी एक ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि अगर न्यायदाता की नियुक्ति प्रक्रिया में ही संदेह और अविश्वास का तत्व समाहित रहेगा तो न्यायतन्त्र पर भरोसा तो डगमगाएगा ही वर्तमान कालेजियम प्रणाली की पद्धति सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय (1993) से विकसित हुई है जिसमें केन्द्र या राज्य सरकार का अभिमत महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124-2 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक जज की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे और वे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजों से परामर्श करेंगे जिसकी व्याख्या पीठ ने इस तरह की है कि परामर्श का अर्थ सहमति होगा और एक अच्छी व्यवस्था तमाम अच्छे विचारों और अच्छे लक्ष्य के बाद भी कालान्तर में पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी का कारण बन गई। इसे बेहतर बनाए जाने के लिए विकल्प के तौर पर न्यायकर्ताओं की नियुक्ति अपने राज्य क्षेत्र के बाहर के उच्च न्यायालयों में किए जाने या अखिल भारतीय न्यायिक के द्वारा नियुक्ति का विकल्प विचारणीय है। न्याय तन्त्र को शुचित और चुस्त करने के लिए यह अति आवश्यक है क्योंकि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए लगना और दिखना भी चाहिए।

वर्तमान संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता परिषद् की भूमिका और भी गंभीर हो जाती है। न्यायतन्त्र की ज्वलन्त समस्याओं के समाधान के लिए अधिवक्ताओं के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और हमारा संगठन एक जाग्रत, क्रियाशील और उत्प्रेरक माध्यम बन सकता है जिसके ऊपर अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बड़ा संगठन होने के कारण और भी बड़ा दायित्व आ गया है। राष्ट्रीय परिषद् की इस बैठक में संगठन के विकास के अतिरिक्त इन सभी ज्वलन्त विषयों पर चर्चा अपेक्षित है। हम कुछ स्मरणीय कार्य करें तभी इस स्मारिका का प्रकाशन भी सार्थक होगा। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छे व्यक्ति बनें, अच्छे अधिवक्ता बनें, अच्छे विचार रखें तो न्यायपालिका के भी अच्छे दिन आएंगे ही।

इस स्मारिका के प्रकाशन से लेकर इस संपूर्ण आयोजन की सफलता के लिए हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पिछले आठ महीनों से लगातार अहर्निश अथक परिश्रम और प्रयास किया है, कोटि कोटि साधुवाद! प्रशंसा के शब्दों का अभाव महसूस करता हूँ पर उन्होंने अपने कर्तव्य और दायित्व का भलीभाँति निर्वहन किया है।

अधिवक्ता परिषद्, बिहार के समर्पित कार्यकर्ताओं के अलावा मैं उन सामाजिक, शैक्षणिक संगठनों यथा—विद्या भारती, संस्कार भारती, भारतीय मजदूर संघ आदि का भी आभारी हूँ, जिन्होंने स्वप्रेरणा से हमारे इन कार्य की सुगम बनाने में योगदान किया है।

और, मेरे लिए तो मेरे सहयोगी उपसंपादक द्वय श्री लकमेश मारविन्द और श्री चेतन कुमार मेरी दो भुजाओं की तरह रहे हैं जिनके सक्रिय सहयोग के अभाव में इस स्मारिका का प्रकाशन संभव नहीं था, उन्हें भी कोटि-कोटि धन्यवाद! स्मारिका का यह अंक आप सबों के हृदय और विचारों में किंचित भी स्थान पा ले तो हमारा यह लघु प्रयास सफल हो जाएगा। धन्यवाद! ■

Er. Sudhir Kumar Singh

B.E. (Civil) B.I.T. Mesra, Ranchi, FIV

Ph. : 2296622 (R)

Mob. : 9431683039

8757514054

**Chartered Engineer
surveyor & Loss Assessor
Govt. Registered Valuer
Income Tax, Patna**

**Flat No.-34/A
Jagat Ambika Apartment
Brahmasthan Road
Sheikhpura, Patna-14**

Valuer of Securities

★ State Bank of India

★ Punjab National Bank

★ Bank of Maharashtra

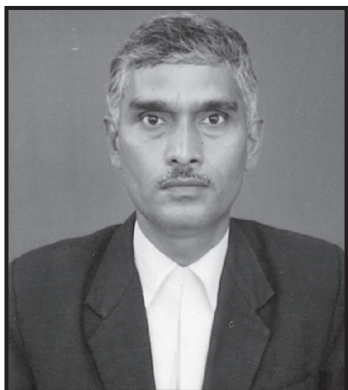
★ HUDCO

★ Canara Bank

★ Bank of India

★ Union Bank of India

अधिवक्ता परिषद, बिहार-एक झलक



सुनील कुमार

अधिवक्ता,
प्रदेश महामंत्री
अधिवक्ता परिषद बिहार

सन् 1992 के दशक में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं के एक ऐसे संगठन की आवश्यकता हुई जो राष्ट्रीय विचारधारा से ओत-प्रोत हो। इस निमित्त भारत के सभी प्रांतों से प्रांतशः करीब 2 से 5, कुल लगभग 300 अधिवक्ताओं की एक बैठक संसद एनेक्सी में अखिल भारतीय स्तर पर हुई जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नामक संगठन को गठित करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के ख्याति प्राप्त अधिवक्ता श्री यु०आर० ललित के नेतृत्व में, माननीय स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी एवं माननीय स्वर्गीय सुदर्शन जी के प्रेरणा से प्रारंभ किया गया। इस बैठक में सांगठनिक कार्यक्रम, विभिन्न न्यायालयों के अधिवक्ताओं से संपर्क एवं संगठन के संवैधानिक रचना पर जोर दिया गया और संगठन का नाम “अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद” पड़ा। संगठन के उद्देश्य के विषय में मा० ठेंगड़ी जी ने कहा कि यह संगठन भारत

का स्थायी संविधान सभा की तरह कार्य करे।

अधिवक्ता परिषद के प्रेरणा स्रोत माननीय स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी का मत था कि संगठन का उद्देश्य और कार्यनीति स्पष्ट हो और उसी के अनुरूप एक संविधान भी हो। प्रत्येक राज्य के अधिवक्ताओं का अपना अलग-अलग संघ हो और केन्द्र का अपना संघ होना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब संगठन की रचना परिसंघ (Federal) प्रणाली पर आधारित होगा। माननीय ठेंगड़ी जी का यह भी विचार था कि संगठन का अपना एक ‘ध्येय वाक्य’ एवं ‘प्रतीक चिन्ह’ भी होना चाहिए क्योंकि इससे संगठन में एकरूपता एवं भ्रातृत्व की भावना प्रबल रहेगी। संगठन के संस्थापक सदस्य माननीय ठेंगड़ी जी के विचारों से ओत प्रोत होकर संगठन के लिए ‘ध्येय वाक्य’ एवं ‘प्रतीक चिन्ह’ तय करने का दायित्व श्री ब्रज किशोर शर्मा जी को सौंपा गया, जो 1990 में भारत सरकार के विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। श्री शर्मा जी ने गहन चिन्तन एवं मनन के बाद संगठन के ‘ध्येय वाक्य’ के रूप में ‘न्याय मम धर्मः’ को उद्घोषित किया एवं प्रतीक चिन्ह के रूप में ‘खिले हुए कमल पर खुली पुस्तक की आकृति का मंडलाकार चिन्ह’ को चुना।

संगठन का ‘ध्येय वाक्य’ के तीनों शब्द पुनीत हैं, पावन हैं, मंत्र के समान शक्ति रखते हैं। इसे सम्मुख रखकर हम मिलकर सामुहिक प्रयास करेंगे तो संगठन के उद्देश्य की सफलता निश्चित है। इसी प्रकार प्रतीक चिन्ह भी अति पावन और पवित्र है, पुस्तक और अधिवक्ता में तो अन्योन्याश्रय संबंध है ही जबकि कमल सदैव निर्मल रहता है, भगवान का चरण, हस्त और मुख की तुलना भी कमल से की जाती है। माता लक्ष्मी भी कमल पर विराजमान रहती हैं जबकि ब्रह्मा, परमपिता परमेश्वर का आसन भी कमल है। अतः अपना ध्येय वाक्य और प्रतीक चिन्ह दोनों ही अति पावन, पवित्र और प्रभावशाली है।

संगठन का दायित्व प्रथम संगठन मंत्री माननीय सूर्य कृष्ण जी, नई दिल्ली, को सन् 2002 में दिया गया एवं इनके नेतृत्व में संगठन दिन दूना एवं रात चौगुणा बढ़ा, श्री कमलेश सिंह, संगठन के दूसरे अ०भा० संगठन मंत्री बने। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रत्येक तीन वर्ष पर भारत के विभिन्न प्रांतों के प्रमुख शहरों में होता आ रहा है। राष्ट्रीय कार्यसमिति

बैठक साल में एक बार अप्रैल माह में एवं राष्ट्रीय परिषद बैठक प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह (Chrismac Holly Day) में होते आ रहा है। राष्ट्रीय टोली बैठक प्रत्येक वर्ष के सितम्बर माह में होता है।

अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की शाखा बिहार प्रांत में भी सन् 1992 में स्थापित हुआ और प्रथम बैठक पटना में आयोजित की गयी जिसमें पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता श्री राम सुरेश राय को संयोजक एवं श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, को सह-संयोजक बनाया गया जिन्हें बाद में बिहार प्रांत के क्रमशः प्रथम अध्यक्ष एवं प्रथम महामंत्री के रूप में दायित्व सौंपा गया एवं श्री हिमांचल नारायण सिंह को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इन लोगों ने मिलकर संगठन विस्तार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बिहार प्रांत के लगभग सभी जिलों में सम्पर्क बना एवं कुछ जिले में सशक्त इकाई भी बनी। इन दोनों व्यक्तियों ने संगठन के लिए अपना तन, मन, धन अर्पित कर दिया और आज उसी का परिणाम है कि अधिवक्ता परिषद का नाम बिहार प्रांत के सभी जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं के बीच अपरीचित नहीं रहा। अधिवक्ता परिषद, बिहार, का द्वितीय अध्यक्ष माननीय स्वर्गीय नर्मदेश्वर झा, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय को बनाया गया है जबकि महामंत्री श्री प्रहलाद प्रसाद चौरसिया, अधिवक्ता, हाजीपुर एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकुल प्रसाद, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय बने। द्वितीय अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष का कार्यकाल भी स्वर्णिम रहा और संगठन विस्तार अधिकाधिक हुआ। संगठन के तृतीय अध्यक्ष के रूप में श्री यदुनन्दन झा, अधिवक्ता, मुंगेर एवं महामंत्री के रूप में श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, पटना सिविल कोर्ट, एवं कोषाध्यक्ष श्री गोकुलानंद सहाय, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय बने। इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 2009 जून में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक महाराणा प्रताप भवन, पटना, में हुई। इस बैठक की व्यवस्था से आगत सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं सदस्य अति प्रसन्न हुए और अधिवक्ता परिषद, बिहार, राष्ट्रीय स्तर पर अपना सशक्त पहचान बनाया। नवम्बर 2012 में चतुर्थ अध्यक्ष के रूप में श्री गौरीशंकर प्रसाद, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर जबकि महामंत्री का दायित्व मुझे मिला। दो वर्ष के कार्यकाल में केन्द्र प्रायोजित एवं प्रांत प्रायोजित सभी कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। वर्तमान में बिहार के 3-4 जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों में अपना सम्पर्क है तथा 7-8 जिलों में प्रभावी कार्य है, जिलों से अपार सहयोग बिहार प्रांत अधिवक्ता परिषद को सदैव मिलता रहता है, जिसके कारण वर्ष 2014 के राष्ट्रीय परिषद की बैठक को करने की भी इच्छाशक्ति प्रांत को जागृत हुई, जिसकी व्यवस्था का आप स्वयं अनुभव भी करेंगे।

प्रांतीय कार्यसमिति २०१२-१५ सत्र की सूची इस प्रकार है-

अध्यक्ष -	श्री गौरी शंकर प्रसाद, मुजफ्फरपुर
उपाध्यक्ष -	1. श्री बिनोद कुमार, दानापुर 2. श्री बिरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, दरभंगा 3. श्री हरदेव प्रसाद, शेखपुरा
महामंत्री -	श्री सुनील कुमार, पटना
मंत्री -	1. श्री ओषित कुमार, भागलपुर 2. श्री आमोद कुमार सिंह, सहरसा 3. श्री शशांक शेखर सिंह, हाजीपुर
कोषाध्यक्ष -	श्रीमती उषा कुमारी, पटना

प्रांत महिला प्रमुख -	श्रीमती शिखा सिंह परमार, पटना
कार्यसमिति सदस्य -	श्री रामनाथ सिंह, दानापुर श्री रतन कुमार सिन्हा, सहरसा श्री राम उचित झा, दरभंगा श्री दिलीप कुमार गुप्ता दिनकर, भागलपुर
विभाग संयोजक -	श्री निर्मल कुमार सिंह, मुंगेर श्री दिनेश चौधरी, आरा श्री प्रवीण दुबे, सासाराम श्री ओम प्रकाश चौरसिया, नवादा श्री महेश प्रसाद सिन्हा, गया
विशेष आमंत्रित सदस्य -	श्री राम सुरेश राय, पटना श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, पटना श्री रणवीर झा 'फूल', सहरसा श्री मोती लाल राय, समस्तीपुर श्री प्रहलाद प्रसाद चौरसिया, हाजीपुर श्री गंगोत्री प्रसाद, छपरा
राष्ट्रीय परिषद् सदस्य -	श्री सुनील सुलभ, पूर्णिया श्री अंजनी कुमार भगत, दरभंगा श्री यदुनन्दन झा, मुंगेर श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

अधिवक्ता परिषद् का मूल उद्देश्य -

- (क) न्याय प्रणाली के विकास के लिए सभी कार्य करना जो भारतीय परम्पराओं तथा भारतीय समाज की चेतना के अनुकूल तथा स्वीकृत संस्कृति एवं ऐतिहासिक परम्पराओं के अनुरूप हो।
- (ख) राष्ट्र की एकता, अखण्डता और प्रभुता के लिए परिषद् पूर्णतः समर्पित है। परिषद् ऐसे सभी सभी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करेगी जिनका उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखण्डता का निर्माण तथा भारतीयों में बन्धुत्व की भावना का विकास करना हो।
- (ग) विधि विज्ञान का संबंधन करना और विधि तथा इसके प्रशासन में उच्च अध्ययन और अनुसंधान का अनन्य और संचालन करना।
- (घ) न्याय और विधि प्रशासन में सुधार तथा जनता की सामाजिक, आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं के उपयुक्त न्याय प्रणाली के विकास का संप्रवर्तन करना।
- (ङ) विधि और विधि प्रशासन तथा उसके आधारभूत सिद्धान्तों का प्रचार करना।
- (च) विधि तथा संबंध क्षेत्रों में सम्बन्धित अध्ययन ग्रन्थों, कृतियों, पुस्तकों, नियतकालिक पत्रिकाओं, निर्णय पत्रिकाओं, अनुवादों

और अन्य संबंधित साहित्य एवं अनुसांगिक प्रकाशित करना।

- (छ) विधि व्यवसाय में लगे अधिवक्ता बन्धुओं, विशेषतया कनिष्ठ अधिवक्ता बन्धुओं से कल्याणार्थ योजनायें बनाना, उनके व्यापक हित संरक्षण हेतु कार्य करना।
- (ज) पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना करना और उन्हें संचालित करना।
- (झ) भारतीय संविधान और विधियों का पुनर्विलोकन करना और उनमें ऐसे परिवर्तन सुझाना जो समाज की सेवा हेतु उन्हें प्रभावी उपकरण बनाने के लिए अपेक्षित हो।
- (ञ) सभी को, विशेषतया समाज के निर्बल वर्ग को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्य करना तथा विधि का शासन स्थापित एवं दृढ़ करने के लिए प्रयास करना।
- (ट) विधि व्यवसायियों को तथा न्यायपालिका के मध्य विधिक रामराज्य को प्रोत्साहित करना तथा प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विरुद्ध जनमत जाग्रत करना तथा उसे मिटाने का प्रयास करना।
- (ठ) उपर्युक्त सभी या किन्हीं उद्देश्य को अग्रसर करने में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समितियों, संस्थानों और संगठन को सहयोग देना और समान उद्देश्यों वाले शीर्षस्थ अखिल भारतीय निकाय के साथ संबद्ध होना।
- (ड) ऐसे सभी कार्य करना जो उपर्युक्त सभी या किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक व उचित हो।

परिषद् द्वारा स्थापित प्रकल्प -

- (क) स्वाध्याय मंडल (Study Circle)

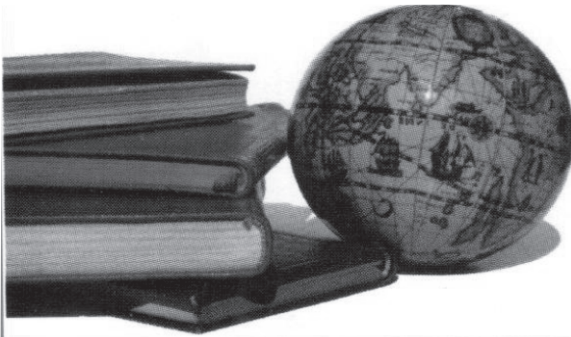
Indian High School (Residential)

Kayastha Tola, Saharsa

(Nur. to +2 Level (Co-ed) English Medium)
Affiliated to be CBSE

**No. 1
SCHOOL**

ADMISSION OPEN



समस्त छात्र-छात्राओं, शिक्षकगण एवं
अभिभावकों को नव वर्ष
की हार्दिक शुभकामनाएँ

N.K. Verma
Director

STRENGTHENING JUSTICE DELIVERY SYSTEM



Mr. Justice Ajay Kumar Tripathi
Judge, Patna High Court

At the very outset I express my thanks to the organizers, Adhivakta Parishad, Bihar, for convening this Conference and giving me an opportunity to share my thoughts and concern for strengthening the justice delivery system of the State to enable it to face the challenges of the 21st century.

Justice is the ultimate objective of law. Access to justice, from an independent and impartial agency is a recognized human right and a prime necessity of a civilized society. Our Constitution injects justice, equity and good conscience into Indian way of life. It is gratifying to note that the architects of our Constitution emphasized to ensure justice to all, even to the poorest of the poor through efficacious justice delivery mechanism. The framers of the

Constitution prescribed the mandate for justice – social, economic, and political, in its Preamble.

In order to achieve the goal of justice, Article 39A has been enshrined in the Constitution with the purpose to provide free legal aid and to strengthen the justice delivery system.

Keeping in view, the philosophy of equality and justice embodies in Part III and Part IV of the National Charter; the Apex Court of the country has also played a vital role through its catena of judgments for the betterment of the administration of justice. Free legal services, speedy trial, *inter alia*, have been declared as fundamental rights and included within the broad matrix of the principle of right to life and personal liberty in Article 21 and right to equality under Article 14.

In spite of these mandates of the Constitution and directions of the Apex Court, the desired goal of the effective justice dispensing system has not been achieved. Indian judicial system has been affected by the problems of legal formalities, rigid procedural rules, delay in justice, corruption, expensive litigation, arrears of cases in all courts, inadequate number of courts, etc.

The docket explosion in India can

be attributed to the faith of the people in the justice delivery system; its transparency and the knowledge that justice will be done one day even though there are delays.

The foremost problem that I have identified is delay in disposal of cases, which not only creates disillusionment amongst the litigants, but also undermines the very capability of the system to impart justice in an efficient and effective manner. Long delay also has the effect of defeating justice in quite a number of cases.

The problem is much more acute in criminal cases, as compared to civil cases. Speedy trial of a criminal case considered being an essential feature of right of a fair trial has remained a distant reality. Steps ought to be taken to quicken pace of justice delivery system.

The real problem is that the institution of cases in the Courts far exceeds their disposal. Though there is a considerable increase in the disposal of cases in various courts, the institution has increased more rapidly.

The Apex Court envisioned a cutting edge solution to the above concern, in the form of Judicial Impact Assessment. According to Professor N.R. Madhava Menon, former Director of the National

Judicial Academy at Bhopal, ***“Judicial Impact Assessment is a process whereby the government can anticipate the likely cost of implementing a legislation through the courts and help deliver timely justice to litigants.”***

Litigation demand depends on a variety of factors most of which are not factored in the making of laws. This results in the court system being left with little or no extra resources to cope with additional cases generated by new laws. This is the main reason why despite increased disposals every year, courts are still crowded with mounting arrears of cases.

Realizing this structural imbalance in the system, the Supreme Court in the ***Salem Advocates' Association Case*** (2005) gave a direction to the government to make Judicial Impact Assessment an essential component of the Financial Memorandum of legislative proposals. The key element in Judicial Impact Assessment is the methodology for estimating judicial workload resulting from new legislations and determining the additional costs involved in Judge-time and support services.

The lack of adequate data on the working of the judicial system, particularly at the level of subordinate courts, has been a serious impediment in planning and management of judicial reforms. We still do not know the exact reasons for delay or the time taken at various stages of judicial proceedings. What is the cost involved in processing different

types of cases and how is it to be calculated? What is the optimum capacity of the system and how judicial time is to be apportioned or evaluated? Management of court systems, including budgeting and accountability mechanisms, is outdated. Given the fact that continuous generation of credible data on court functioning is the foundation for Judicial Impact Assessment, it is imperative that a mechanism for collection, analysis and reporting of judicial data is put in place at the earliest.

I also wish to make certain further suggestions in other fields, as follows –

Criminal

- The institution of Special Public Prosecutors needs to be strengthened. The remuneration / fees of the Special Public Prosecutor is considerably low and it should be enhanced to attract experienced, committed and knowledgeably advocates.
- There should be time limit for investigation by police and conclusion of the trial.
- The attendance of I.O.'s at the hearing ought to be stricter; missing a hearing must not be an option.
- Sensitization and periodical orientation sessions for police personnel, judicial officers, Public Prosecutors must be held.
- Providing better incentives to judicial officers to attract talent will be one way of strengthening the system.
- Enhancing capacity of judicial officers and public prosecutors through training programmes and supporting creation or strengthening of a judicial academy in each state to facilitate such training.

Alternative Dispute Resolution

Strengthening of ADR mechanism is vital. ADR will be a success here because the aim is to resolve a dispute and not to decide the dispute.

- The Delhi High Court established the Delhi International Arbitration Centre (formerly Delhi High Court Arbitration Centre) on 25th November 2009. The Patna High Court may also set up an ADR center, in terms of Section 89 of the Civil Procedure Code, in each judicial district, which is without an ADR center.
- The ADR mechanism should be strengthened, achieving the twin objectives of speed with cost effectiveness.
- The time and cost effectiveness maybe achieved by a Core committee / Advisory committee, comprising of trained legal professionals / advocates (who volunteer and may eventually be paid), who monitor the

entire process of arbitration from inception till the end. The Core committee can be backed by an efficient Secretariat to achieve the objective of time effectiveness.

- A set of Rules ought to be framed for the ADR centers, balancing and respecting the fundamental principle of party autonomy.
- An in-house mechanism should be established in the government for amicable settlement of such case where government was a party.

Lok Adalat and Legal Aid System and Other / Special Courts

- Enhancing support to Lok Adalats will reduce the pressure on regular courts.
- Legal Aid system should be made accessible and affordable to the poor and weaker sections.
- There should be a fuller and more fruitful implementation of the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987, which has been enacted to provide free legal services to the weaker sections of the society and to organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes.
- Local human rights organizations / NGOs, elected representatives, and law students, should also be actively involved by National

Legal Service Authorities (NALSA), constituted under the 1987 Act, at grass-roots level for enhancing legal awareness of vulnerable groups.

- Unless the advocates provided (by legal services authority) are competent and hard working, no useful purpose is served by making their services available to the poor litigants. Legal Service Authorities have to take suitable steps to ensure that they empanel only counsels of proven ability and integrity, in whom the poor litigants may repose trust. Legal services authorities should ensure that such panels are managed only by service oriented advocates and are not used for the purpose of doling out favours and merely for the purpose of earning livelihood.
- Legal literacy will make the citizens aware of their legal rights and obligations, including their right to receive legal aid from the State. Those trained with legal education can work to increase legal literacy amongst the people, which is where involving students from various law schools in each state becomes important. The services of law students can be effectively utilized in spreading legal literacy and facilitating negotiated settlement of disputes.

- For the better performance of the Special Courts and to improve the rate of conviction, the Chief Justices of the respective High Courts should depute Justices of the High Court to review the working of the Special Courts and judgments delivered by Special Courts, at least once in a year. The judicial review would highlight all those legal and administrative aspects / facts responsible for acquittal of accused, weak prosecution and the quality of the judgments.
- States may set up morning / evening / shift / weekend / mobile / special magistrate courts, to try petty cases so as to clear the backlog of cases and to relieve pressure on judicial time – these Courts may either utilize the services of regular judicial officers on payment of additional compensation or retired officers.

Other

- Increasing the strength of judges in various courts and augmenting the infrastructure, will also aid the resolution of the ever-increasing caseload.
- If judgments at the level of trial courts are of a high quality, the number of revisions and appeals may also get reduced. The training needs to include Court and Case Management

besides methods to improve their skills in hearing cases, taking decisions and writing judgments, removing the potential inconsistencies and conflicts in judicial decisions, getting acquainted with the changes in laws, finding grey areas where the existing laws need modification and/or to interpret the laws in accordance with new international treaties and covenants, etc.

- Creation of the post of Court Managers in every judicial district to assist the judiciary in their administrative functions.
- Before assuming office as the Chief Justice of India, Mr. Justice Lahoti (Retd.) had observed that information technology had a major role to play in the justice delivery system, particularly in the area of issuing order copies by way of digital signature.

Conclusion

I would like to conclude by saying that the main challenges we face for ensuring justice dispensation to everyone in this country need to be tackled by understanding the following –

Firstly – Effective justice dispensation through the courts requires at least three elements:

- Access to courts,
- Effective decision-making by

judges, and,

- Proper implementation of those decisions.

A law that is healthy and vital is shaped from the context in which we live. It is in the individual cases where the hard choices are made, our legal principles crystallized, and our faith in justice reaffirmed. If people do not have access to courts at all levels of the judiciary then we are missing voices, problems, and perspectives that enrich the ideals of the law enunciated at the top or at any other level of the judiciary. Our ideals of justice are not so much created and refined by logic as they are by experience.

Secondly – A crucial obligation also becomes that of the government; to ensure timely and responsive justice to the public and also to provide them the right guaranteed under Article 39A of the Constitution (i.e. to provide equal justice and free legal aid and to provide opportunity to all for “Access to Justice”).

The efficiency and effectiveness of any State is undoubtedly measured by the successful coordination between its three organs, and “Access to Justice,” should be the joint concern of judiciary and the state government. It is said that, not only must justice be done; it must also be seen to be done. Such a standard of perfection can be achieved only if all the organs involved in justice delivery system are well equipped with infrastructures, tools and legal and

scientific literature, which need refinement, updating and replacement from time to time.

Thirdly – Lawyers are responsible for building upon whatever gains we have made in justice dispensation; repair our errors; and defend those democratic institutions, which are needed for justice dispensation, and hence have a critical role to play. Former attorney general Soli J. Sorabji had said, *“Law is a service-oriented profession and not a commercial undertaking. There must be a realization for every lawyer that in essence we all are rendering a service to society.”*

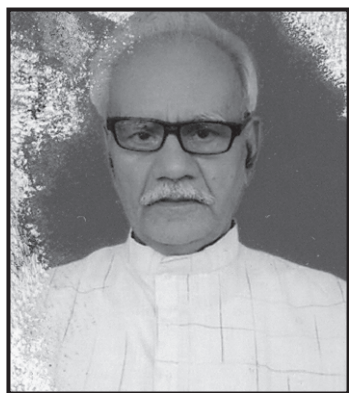
Lawyers must view themselves as public servants no matter what their chosen field of practice; no matter what side they take on a case. The law that you invoke is not yours; it is of the people.

Self-realization, self-criticism and self-judgment are the three angles of any reforms. With my suggestions above, a road map has been laid-out. All that is required now is to follow it up with zeal and enthusiasm to achieve the desired goal.

Thank you all.

Writer is the Hon'ble Judge of the High Court of Judicature at Patna. Delivered speech on the occasion of constitution day celebration held at Bihar Industries Association Hall, Patna, on 26.11.2014 ■

Good Legislations for farmers in bad hands of Executive



Ram Suresh Roy
Sr. Advocate
High Court, Patna

The three legislations namely;

1. Bihar Land Reform Act, 1950
2. Consolidation Act 1956
3. Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961

were passed with pious objective to remove intermediaries from the socketed bond of farmers and State, for which a notification vesting an estate or tenure in the State by virtue of section 3 of the Land Reforms Act with further condition that rights acquired by a person by virtue of settlement of lands including Gair Majarua Aam Land by Landlords that categorised/ person of the status of a raiyat and can not be defeated by provisions of Land Reforms Act. Settlee of Gairmajarua Aam lands including Gair Majarua Malik lands acquired occupancy right in such lands acquired by them.

This is a provision under section 4(H) of the Land Reforms Act. Power was given to the Collector for enquiry of settlement done after 1947. Then there is also a provision under section 6 of the Land Reforms Act that any Gairmajarua Malik land if in khas possession of landlord will be deemed to have been settled with the ex-landlord as a raiyat. The entire implementation of the said Act was to be based on revisional survey to know about actual possession of the raiyat after cadastral survey which concluded in the year 1911.

The Circle Officers started collection of rent from the date of vesting which ended between 1950 to 1955, but the executive agency collected rent on the basis of return filed by the ex-landlords, the receipts were being issued with word without prejudice. The Circle Officers and Karamchari started to issue such rent receipts arbitrarily on getting some money from the farmers without any authentic record. So far returns filed by the ex-landlords in course of time after payment of compensation, either kept haphazard as or they became traceless.

The revisional survey proceeding started in the year 1962-63 and officially concluded in 1972-73. The revisional survey authorities placed reliance on cadastral survey document which concluded in the year 1911. They simply ignored as to what

happened from 1911 to 1950 when the Land Reforms Act was passed. Virtually ex-land Lords settled entire Gairmajarua Malik land in favour of raiyats, the residuary lands were settled by the ex-Landlords before passing of the Act with raiyats for getting compensation over those raiyati lands. It is also to be noted that the survey Department of State of Bihar issued administrative letter to the survey authorities that "Remember the fact that this is a revisional survey not original survey", as the estate has entered into the shoe of ex-landlords and all Gairmajarua Malik lands should be recorded in the name of State of Bihar. This simple direction created havoc and during survey large number of Revenue suits were filed challenging such revisional survey entries. While the suits were pending an amendment was made in B.T. Act that all suits will be transferred from Civil Courts to settlement Officers, some of the raiyats challenged the said amendments i.e. section 109(1) (D) and section 2 of the B.T. Act. The said amendments was quashed by the Hon'ble High Court, Patna Reported in AIR 1974 (Patna) 164 (F.B.).

Now again the cases were transferred from settlement officers to the civil courts and in the meantime a notification was issued under the provision of section 3 of the Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act 1956

for the entire State of Bihar. The effect of the said notification was under the provision of section 4 of the consolidation Act, all suits pending in civil courts, even recording correction of revenue records stood abated and transferred to Consolidation authorities. Thus in view of the aforesaid development the problems of farmers regarding illegal preparation of record of rights in revisional survey published in the year 1971-72 were never solved by a competent authority deciding right, title and possession.

The result of the said non-adjudication of dispute regarding title and possession of the raiyats resulted mass corruption before the consolidation authorities and the Executive earned crores of rupees and became rich at the cost of poor farmers as they got free hand in deciding such

dispute.

So far wrong implementation in ceiling Act is concerned, section 4 of the Ceiling Act defines area of 15 acres even irrigated by private lift, 25 acres in orchard etc., 37½ diara land, 45 acres hilly and sandy area, while defining family, section 2(F) Defines" land means land which is used or capable of being used for agriculture or horticulture and includes land which is an orchard, Kharhur pasture or forest land or even land perennially submerged under water or Home stead of a holder. In other State like Bengal, Home Stead is not included. In U.P. Orchards are not included. Further a fixed date i.e. 9.9.1970 as last date for deciding nature of land and family members.

It will not be out of place to state here that authority never imagined that

in near future in Sone Canal there is Rehand Dam, Bansagar Dam also came in existence. Later on blocking water supply constructed on the same river at Indrapuri. Earlier Sone canal was supplying water through out the year, but now it has become a canal which can feed the area only for one crop. The class I area was defined which receives water through out the year. Now after construction of two barrage in Sone river the Sone canal supply water only in one season on the other hand classification of area was Gandak and Kosi project canal they will remain as usual and supply of water to those farmers can not be considered for classification of land as irrigation started after 9.9.1970, the fixed date so a curative approach in the affairs now has become imperative by the welfare state of the province of Bihar. ■



An ideal school based on Indian Culture

GANPAT RAI SALARPURIA

SARASWATI VIDYA MANDIR

(Affiliated to C.B.S.E, New Delhi upto Senior Secondary (10+2 Level)

NARGAKOTHI, CHAMPANAGAR, BHAGALPUR (BIHAR)

PH. 0641-2900134, MOB.-09835420514

Email-ID: grssvmbgp@gmail.com / grssvmbgp@rediffmail.com. Website: www.grssvm.org

Salient Features :-

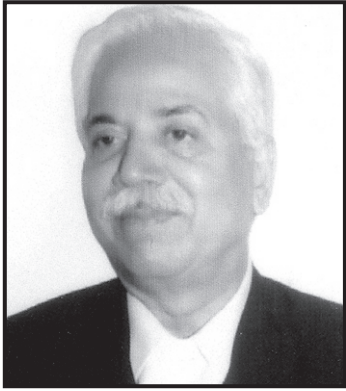
- ❖ Prime Co-educational institution with quality teaching and discipline.
- ❖ High standard Education from Nursery to XII classes.
- ❖ Highly rich Library and full equipped Science & Computer Labs.
- ❖ Teaching by proficient & qualified teachers on recent C.C.E pattern of C.B.S.E.
- ❖ Stress given on all round development, personality and character building of students.
- ❖ Eco-Friendly Environment.
- ❖ Excellent games & sports facilities namely Volleyball, Handball, Badminton, Kho-Kho, Kabaddi etc. Expanded & attractive garden.
- ❖ Digital (Smart) Class room facility for all.
- ❖ Hostel Facility is also available (For boys only) class IV to Xth

Dr. Chhote Lal Das
Secretary

Sanjay Kumar Singh
Principal



Gair Majarua Aam & Gair Majarua Khas



Keshav Shrivastava
Sr. Advocate
High Court, Patna

Gairmajarua Aam and Gairmajarua Khas / Malik are terms pertaining to nature of lands. Although they are terms used in Urdu Language, they are so commonly used in the State of Bihar that the necessity to go into its meaning hardly arose in Zamindari days. However, Urdu not being so frequently used by the post Zamindari Generation, the need to know its actual meaning is being felt more and more.

The word 'Gair' means 'without' or 'other than' and the word "Majarua" means cultivated or cultivable. Hence Gairmajarua would mean such land which is uncultivated or not cultivable. Further 'Aam' means common and Khas or Malik means of the Malik or landlord exclusively.

Applying this meaning to the term "Gairmajarua Aam" it is clear that it pertains to that kind of uncultivated part of land which is in common use of the Public or raiyats of a village. Such

lands vested in the state of Bihar upon vesting of Zamindari and were recorded as Gairmajarua Aam Bihar Sarkar or Gairmajarua Sarva Sadharan in the Revisional Survey Record of Rights.

Similarly, Gairmajarua Khas / Malik lands are in the nature of such lands which are not cultivated by any raiyat hence remain parti and are recorded as "in khas (exclusive) possession" of the landlord or Malik.

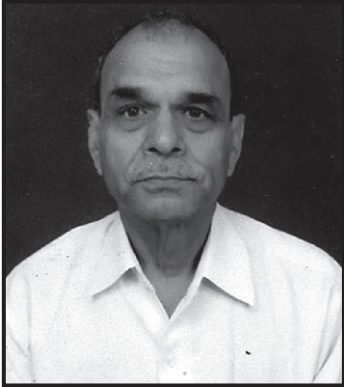
Usually, Gairmajarua Aam lands are commonly used as village Roads, ponds which are used for bathing of villagers and domestic animals and for irrigation and also for worship in temples constructed by villagers over such lands, for cremation etc.

The general rule is that the Gairmajarua Aam land, if they are recorded as such in the Cadastral Survey / Revisional Survey Record of Rights (Khatian), they cannot be settled or transferred through sale deed by the landlord to any raiyat. But over the years the Courts through their pronouncements have held firstly, that the landlords were competent to settle or transfer through sale deed those portions which were not in common use. Secondly, with the long lapse of time any Gairmajarua Aam land may undergo physical changes and may also lose the nature of use due to which it was termed as Gairmajarua Aam and in such circumstances such lands could be settled or transferred by the ex-landlords during the period prior to

vesting of Zamindari under the provisions of Bihar Land Reforms Act, 1950. Thirdly, it is now also the policy of the government of Bihar that Gairmajarua Aam lands or Gairmajarua Khas / Malik lands which even, after vesting of Zamindari, are recorded and continuing as such, can be settled with the Maha Dalit families out of which 50% beneficiaries should be ladies.

So far as Gairmajarua Khas or Malik lands are concerned, if the Malik or ex-landlord has shown these lands in its Zamindari Return filed at the time of vesting of Zamindari as required under Bihar Land Reforms Act, 1950 as being in his Khas possession or cultivating possession, he was required to file a petition under section 6 of the Bihar Land Reforms Act, 1950 to retain such lands as raiyats under the State of Bihar after fixation of Rent. Thereafter, the said land would be deemed to be settled with him and he will get all transferable rights in the said land as a raiyat. However, the Gairmajarua Khas lands of those ex-landlords who do not file Return in respect of their lands vest in the state and do not get recorded in the name of the Ex-landlord the state becomes the owner and custodian of such lands and puts it to any use, it deems necessary in the public interest or in the interest of landless or Dalits, or Maha Dalits in pursuance of its goal of pursuing the policy of running a welfare state. ■

Demand of the Day



Rabindra Kumar Sinha
Advocate
Civil Court, Patna

Now a days senior citizens have become a big problem through out the world. With this problem in view, several bills have been formulated on national and international level, UNO announced a Declaration of the Rights of Older persons in 1991. 1st September was decided to be the world Alizimer Day. A Report on detailed study of problems of senior citizen was brought on the Table. Other countries also formulated several

laws in favour of senior citizen.

India also felt a need of an act for eradication of senior citizens problem. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior citizens Act was passed in 2007. In this Act stress was laid on the well beings of parents and Senior Citizens. A National Policy for the welfare of senior citizens was announced in 1999, by Govt. of India. The Act of 2007 was hold good in different states of India on different dates. Bihar Govt. also introduced Bihar Maintenance and Welfare of Parents and Senior citizens rule-2012. It took years to come on ground level. In June 2012, the Chief Secretary of Bihar ordered all the DMs and SPs through a letter to bring the act to practical level. The work on practical level has started now though in a slow speed but with a bright future.

Brief Introduction of the Act.

- The maintenance and welfare of parents and senior citizens Act 2007 seeks to make it a legal obligation for children and heirs to provide maintenance to senior citizens. It also permits state Government to establish old age home in every district.

- Senior citizens who are unable to maintain themselves shall have the right to apply to a maintenance tribunal seeking a monthly allowance from their children or heirs.
- State Government may set up maintenance tribunals in every sub-division to decide the level of maintenance appellate tribunals may be established at the district level.
- State Government shall set the maximum monthly maintenance allowance. Monthly allowance may be at Rs. 10,000/- per month.
- Punishment for not paying the required monthly allowance shall be Rs. 5,000/- or upto three month imprisonment or both.

The present Act is a welcome step and is a must because of the following reasons :-

- Rise in life expectancy.
- Breaking of joint family System.
- Rise in cost of living.
- Blind copying of western culture.
- Lack of education to respect elders and erosion of traditional values.
- Financial and social insecurity of older person. ■

With best complements

from

Dr. L.K. Sahay

Bhagalpur

Mob. No.-09431090330

Temporary Provision of Article 370 of the Constitution of Bharat How Long to Exist?



Pramod Kumar Sinha

Advocate
High Court, Patna

Indiscriminate but premeditated cross border prolonged firing perhaps heaviest after 1971 Indo-Pak war, shocked the people of Bharat and put a question mark on the capability of the new Sri Narendra Modi led Govt. in dock. But a mighty positive counter attack of our B.S.F gave we people of Bharat a heave of sigh when we heard that Pak took initiative in the direction of holding a flag meet. Pakistan, a creature on the plinth of religious hatredners, has always taken Bharat a soft state to divert the attention of its people from its own burning problems and unbearable disturbance, and we people of Bharat, though not in numbered, are also in dilemma on the status of Jammu & Kashmir.

History of the territory of

the State of Jammu & Kashmir needs not to be traced in too past. But just after coming of the reign of British India, its territorial history needs to be noticed. The province of Jammu & Kashmir comprises mainly of three regions, namely Kashmir region, Jammu region and Ladakh region. Kashmir region was under Sikh rule whereas Jammu and Ladakh regions were under Dogra domain and after the defeat of Sikh, two treaties were executed; first treaty at Lahore was signed in between Sikhs and the British Government on 09.03.1846, whereunder the Sikhs submitted its certain areas to the British Govt. on account of their inability to pay the indemnity of ₹one and half crore, and the second known as Amritsar treaty, executed in between Raja Gulab Singh of Dorga dynasty and British Govt. on 09.03.1846 whereunder British Govt. transferred Kashmir region to Dogra dynasty and the entire State of Jammu & Kashmir thus come under the control of Gulab Singh as the princely state under the treaty of paramountcy but under the pervasive administration of the British Govt.

There were strong freedom movement in the country under the umbrella of Indian National Congress and other revolutionary patriotic organizations. But in the

province of Jammu & Kashmir a political organization was founded by Sheikh Abdullah targeting mainly against the reign of the it's Maharaja with a quit Kashmir slogan and Pandit Nehru took Sheikh Abdulla as mass leader of Jammu & Kashmir, representing the wishes of the people at large which became the core of differences between Pt. Nehru and Mahraja Hari Singh, and perhaps was the reason, the Maharaja remained in the State of Indecisive, after coming in to force of the Indian Independence Act, 1947, in as much as the treaty of paramountcy of the princely states of Bharat with her majesty came to an end and Jammu & Kashmir like other princely states of Bharat became free in its choice to accede either to Bharat or to Pakistan or remain Independent. Maharaja intended to remain independent. Bharat became independent on 15th August 1947 and due to indecisive attitude of the Maharaja, Pakistan took advantage to grab entire Kashmir and in the guise of tribal, virtually Pakistani Army entered in to the territory of Kashmir by causing heavy bloodshed which enlightened Maharaja Hari Singh to send letter of accession dated 26th Oct. 1947, of the province of Jammu & Kashmir to Bharat to Lord Mountbatten with clear wordings 'I

attach the instrument of Accession', which accordingly was accepted on 27th Oct. 1947. The decision of Maharaja to accede to Bharat did not put any condition but its synchronal acceptance by Lord Mountbatten was conditional with the text 'it is my Govt.'s wish that as soon as law and order is restored to, and its soil become free of invaders the question of State's accession should be settled by a reference to the people'. Our army stepped on the soil of J & K and fought bravely against Pakistani counterpart and we committed blunder in taking matter to United Nation on 1st Jan. 1948 and the U.N. resolution dated 13th Aug. 1948, embarked cease fire with a mandate upon Pakistan to withdraw its all type of forces and Bharat to seize down it's forces. Pakistan even after cease fire refuted this U.N. resolution and did not withdraw its forces and by the way Pak occupied Kashmir is still out of the territory of Bharat.

On 26.11.1949, Constituent Assembly of Bharat adopted the Constitution of Bharat under which some of the provisions of the constitution of Bharat became enforceable at once and the remaining provisions came to be enforced on and from 26.01.1950, and enforcement further of Constitution (Application to Jammu & Kashmir) order 1950, the State of Jammu & Kashmir became the integral and inseparable part of our Bharat and the Jurisdiction exercised by Maharaja over it dissolved. The most controversial provisions of Article 370 of our Constitution under the title

"Temporary Provisions with respect to the State of Jammu & Kashmir" makes the State of Jammu & Kashmir a villain in the eyes of the People of rest of Bharat, under which the provisions of Articles 238 became inapplicable so far as the State of Jammu & Kashmir is concerned though it is a part B-State. The day, on which the Constitution of Bharat came in to force, there was no Constitution of the State of Jammu & Kashmir. On 31.10.1951, the Constituent Assembly of Jammu & Kashmir came in to existence and the said Constituent Assembly adopted the draft of the Constitution of Jammu & Kashmir on 17.11.1956 and it became effective on and from 26.01.1957, with the provision as provided in its section-3, that Jammu & Kashmir an integral part of Union of India with the territory as was on or before 15.08.1947, which includes the territory of Kashmir now being occupied by Pakistan. But its preamble does not mention the word 'socialist secular like preamble of the constitution of Bharat inserted by way of subsequent Constitutional amendment.

The position that emerges of the conjoint existence of the Constitution of Bharat vis-à-vis the constitution of Jammu & Kashmir, is that any amendment made in the Constitution of Bharat shall have no effect in relation to the State of Jammu & Kashmir unless applied to by way of presidential order under the provisions enshrined in Cl.(1) of Article 370 of the Constitution of Bharat subject to its concurrence by the Govt. of the State. Bharat's

Parliament's Jurisdiction to the State of Jammu & Kashmir becomes confined to the matters enumerated in Union List, and concurrent list that too subject to certain modification and no State List is applicable in the State of Jammu & Kashmir, besides these anomalous situation the more Constitutional disaster is that even the residuary legislative Power of the Parliament of Bharat like other states, is not enforceable on the State of Jammu & Kashmir, but vests that in the legislature of that State with exception relating to certain matter specified in 1969.

Much hue and cry is raised that the State of Jammu & Kashmir is an integral part of Bharat but the irony is what's a kind of integral part it is? No State like the State of Jammu & Kashmir is ruled under its own Constitution but ruled under the Constitution of Bharat. After sacrifice of the life of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, at least Sheikism established by Late Sheikh Abdullah could be minimized somewhat. After Bangladesh war, Late Mrs. Gandhi should be complimented for her efforts of the well known Shimla agreement, signed on 03.07.1972, which withdrew completely the Jammu & Kashmir problem from the domain of U.N. and made it a bilateral one, though that was the time when Late Mrs. Gandhi could have solved this problem finally.

Recent disastrous flood came in the province of Jammu & Kashmir must have opened the eyes of the people of the State particularly the efforts of rescue operations taken by the Govt. of

Bharat under the Leadership of the Hon'ble the Prime Minister of Bharat Sri Narendra Modi that neither Pakistan nor separatist forces nor Hafiz Sayeed, who even in such disastrous situation instead thinking of the device of rescue and relief, remained engaged in accusing Bharat for the cause of the said disastrous flood, could think their well being. The State of Jammu & Kashmir has gone to a chain of assembly and Parliamentary elections which show their commitment to the democratic process of alignment with Bharat but for complete

assimilation of its brotherhood with the brotherhood of Bharat now time has come that people of the State of Jammu & Kashmir should come forward and make demand of complete repeal of the Constitution of Jammu & Kashmir and more particularly Article 370 of the Constitution of Bharat. Though solution on Judicial side is in demand but spontaneous will and courage of the people of Jammu & Kashmir would be better. Unless Constitution of Jammu & Kashmir is scraped completely and the State is brought directly under the rule according to the provisions of the

Constitution of Bharat like other states of Bharat, with complete scrap of Article 370 of the Constitution of Bharat, how it can be said that the province of Jammu & Kashmir is an integral part of Bharat.

One answer to the core question is, as to how long a temporary provision of Article 370 should exist in our Constitution, has to be given both by the People and the Govt. of Jammu & Kashmir, and the Union Legislature?

Author is an advocate of Patna High Court and Spl. Invitee of National Executive Committee of Akhil Bhartiya Adhivakta



Affiliation No: 330142

School Code: 50051

Pujya Tapaswi Shri Jagjeewan Jee Maharaj

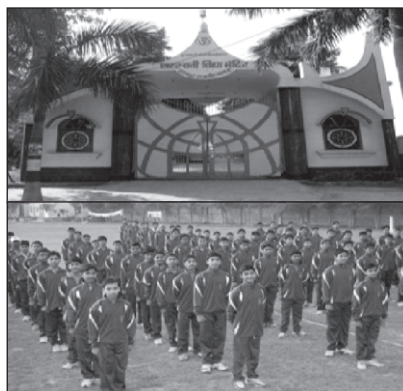
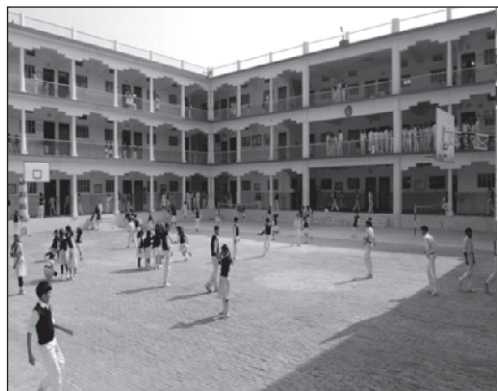
Saraswati Vidya Mandir

Hasanpur, Rajgir, Nalanda, Bihar
Senior Secondary School affiliated to CBSE, New Delhi



Website: www.ptjmsvm.in
Mobile: 9431015787

Email: ptjmsvmmandir@gmail.com
FAX: 06112-256808



Salient Features

- Co – Education from Nursery to XII
- Medium of Instruction : English
- Rich Library
- Smart Class Facility through Teach-Next and Tata Class Edge in all class rooms.
- Boarding Facility for Boys of Classes IV to X
- A grand record of Board Results
- Vehicle Facility available for Day Scholars
- Registration for Admission in classes NUR to VII begins from December
- Registration for Admission in class XI begins from last week of April.
- Language Labs, Maths Lab, Soc. Sc. Lab to be in function from next session
- Separate Hostel Blocks for Classes IV to V, VI to VIII & IX to X
- A team of well qualified, trained and experienced teachers
- There are many Botanical Garden
- Well –equipped Science & IT Labs

(Ramendra Rai)
Secretary

(Jagrit Bhanu Prakash)
Director

(Sumant Kumar)
Principal

Consequences of Non-deduction, Non-deposit and Late Deposit of Tax Deducted at source under the Income Tax Act.



Shivnath Pd. Agrawal

Advocate

Daltonganj, Jharkhand-822101

To know the consequences of Non-Deduction of T.D.S. and thereby non-deposit of the same into the head of Govt. Revenue and if the T.D.S. is deducted but the same has not been deposited into the Govt. A/c in time as prescribed under the law the same is discussed hereunder.

First of all it will be discussed that what will be the consequences under the Income Tax Act if deduction of TDS is not done. There are so many heads under the Income Tax Act upon which, tax is deducted at source but in this article general points are highlights in this regard only.

Non-Deduction of T.D.S.

Chapter XVII of the Income Tax Act 1961 deals with collection and Recovery of Tax. Section 190 of the Act deals with Deduction at source and Advance payment. According to this

section, the regular assessment of Income is to be made and the tax shall be payable by deduction. Section 191 deals with; If the deduction of tax has not been made, the tax payer shall pay the tax directly.

If the deduction of tax is not done as required under the law or if the tax payer does not pay the tax directly, then the consequences will be that the deductor of tax or depositor of tax, both will be deemed vividly to be in defaults as per Subsection (1) of Section 201 of the Income Tax Act, 1961.

Non Deposit of tax deducted at source :

Deduction of tax as made at source is one of the important obligation on the part of the tax payer and the deposit of the amount so deducted in the account of the Government Machinery within time as provided under the law is also very important. If the deductor fails to deposit the amount so deducted, a serious consequence may arise and the Income Tax Department may take suitable action under the provision of law.

Section 200 of the Income Tax Act, 1961, provides a duty on the part of the person to deduct tax at source and to pay into the account of the Government within the time prescribed as per Rule 30 of the Income Tax Rule.

If a person deducting the amount

of tax, but does not deposit into the account of the Government head then the deductor shall be liable to face the consequences viz. (1) to pay interest as per Section 201(1A), (2) to pay penalty under the provision of Section 221, (3) to be charged under sub section (2) of Section 201, (4) to be disallowed the amount of expensed as claimed as per Section 40(a) (i) and 40(a) (ia) of the Act and at the end (5) Prosecution proceeding may be initiated under the provision of Section 276 B under the Income Tax Act.

Section 276B is a penal Section punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to seven years and with fine also.

It is also very necessary to note here that the amount of tax deducted at source but not deposited by the deductor then the same amount cannot be recovered from the person from whom the amount was so deducted as per Section 205 of the Income Tax Act. The tax payer will not be charged or punished if the deductor of the tax at source fails to deposit the same in the account of the Government head.

Section 205 clearly provides that the tax deducted at source, the same can not be recovered again.

Late deposit of the amount so deducted at source :

The last stage is that the amount of tax so deducted at source and the deductor of the amount fails to deposit the same into the credit of the Government Machinery in time, what consequences are provided under the Income Tax Act.

For non-deposit of the deducted amount, there are several provisions as stated above even at the end prosecution provision is provided as per Section 276B of the Income Tax Act. Not only that the tax payer is free from the liability as per section 205 of the Act. There are several decisions of the High Courts in support of it also, but in the cases the deductor of the tax deducted at source deposits the

deducted amount with interest as per Section 201(1A) of the Act, the initiation of penalty proceeding under Section 221, prosecution proceeding under section 276B or any proceeding of any nature will not continue. If any proceeding has been initiated and the deductor of tax at source has deposited the amount with interest for late deposit of deducted amount under the provision of Section 201(1A) of the Income Tax Act, the said proceeding will come to an end itself. The Deptt. will not put to loss if tax with interest is paid in toto.

It is also very necessary to keep in mind that there should not be any malafide intention in depositing the

amount of TDS by late. The depositor may be precluded by some reasonable cause in depositing the TDS in time. Reasonable cause for late deposit of TDS must be kept in mind before taking any adverse view in the matter.

The deposit of TDS with interest voluntarily by the late Depositor itself proves his integrity, honesty and sincerity. So intention of the late Depositor of T.D.S. must be considered reasonably and honestly. The law does not permit to the Authority of the Income Tax Department to punish or charge any person unnecessarily without scrutinizing the matter in details or to going beyond the provision of law. ■



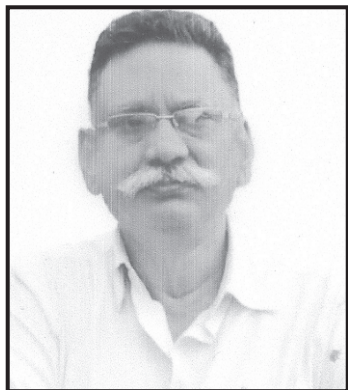
AIR CELEBRATING 100 YEARS OF SUCCESS

<u>JOURNALS</u>	<u>COMMENTARIES</u>
ALL INDIA REPORTER	CPC BY CHITALEY IN 6 VOLS
CRIMINAL LAW JOURNAL	LIMITATION ACT IN 2 VOLS
LABOUR INDUSTRIAL CASES	EVIDENCE (SINGLE VOL)
SUPREME COURT WEEKLY	TRANSFER OF PROPERTY ACT (SINGLE VOL)
AIR SC CIVIL	CONTRACT ACT (SINGLE VOL)
AIR SC CRIMINAL	MARRIAGE & DIVORCE ACT (SINGLE VOL)
AIR CIVIL CASES	HINDU LAW IN 2 VOLS
	PENAL CODE (SINGLE VOL)
	AIR DIGEST SERIES

AIR COMPREHENSIVE SOFTWARE 1950-2013 & PRIVY COUNCIL 1900-50
AIR WEB WORLD

Contact : Office
0612-2505737, 9835259454,
9835259464, 9835607836

The Ghost of Khas Mahal



Amar Sinha
Advocate, Munger (Bihar)

To understand the origin in-short of "Khas Mahal" one can understand that the ESTATE OF KHAS-MAHAL belonged to the Mughal Emperor himself.

Mughal Emperor Farukh Siyar permitted the British East India Company to acquire zamindari rights in different Khas Mahal villages i.e. the Company got the "Right to Rent" and nothing else.

From Company this "Right to rent" vested in the Secretary of state for India in council - after the administration of India was taken over from it by Statute of the British Parliament in 1858 – first being Lord Stanly appointed as such on 02.08.1858.

As, lease of Khas Mahal is operating under T.P. Act, where there is no rule-making power

vested to the State Govt. and which is a superior legislation covering the whole filed, the vested rights to the lesses/Tenants/ absolute propriors can not be taken away except under authority of law. These rule making power of State Govt. without the support of a legislation / ligislative enactment is not capable of achieving such an ends as Khas Mahal Policy 2011.

As per the Division Branch decision of the Hon'ble Calcutta High Court in Appellate Civil before Guha and Lodge J.J., Secretary of State for India in Council

Vrs.

Lal Mohan Chaudhari reported in 1935 I.L.R. Vol. LXIII. Calcutta series. The Hon'ble court held that Khas Mahal is not a Crown Grant, (i.e. not under Govt. Grants Act.)

It was held that, "The position of the Government in regard to Khas Mahal lands is that of an ordinary land lord, the Government occupying no higher positions than that of a Zamindar;the Government being in possession of that Mahal merely as a private proprietor." With the enactment of the Bihar Land Reforms Act, 1950, Govt. of Bihar decided to take over all the Zamindaries and tenures in Bihar. In Monghyr district by

Notification no. 5404-L.R. dated the 21st September, 1954; another notification was no. 5404 L.R. dated the 21st Sept. 1954 and then yet another notification no. 631 L.R. dated 26th Jan. 1955, all Zamindari interest were vested in the state of Bihar with full protection to occupancy right of tenants.

The position with regard to Govt. estates in the district had now changed and they also vested in the State Govt. with effect from 26.11.1955.

The lessees are absolute owners and proprietors of the Town Khas Mahal lands properties and the State is competent of collect the rent only, and protect the occupancy rights of the tenants/ patta holder.

The Hon'ble Supreme Court of India in state of U.P. v/s Zahoor Ahmed and others, reported in 1973 AIR2520 = 1973 SCC (2) 547, concurred in its judgement delivered by SIKRI S.M. (C.J.) and PALEKAR, D.G. (J) – "On the other hand, there is an illustration of what is not a Government grant within the meaning of the Government grants Act. The decision in secretary of State for India in councilv/s Lal Mohan Choudhuri I.L.R. 63 CAL. 523 furnishes that illustration. The Government in the

case granted lease in respect of Khas Mahal Lands. The lease of Khas Mahal was held not to fall within the category of grants as contemplated in the Crown Grants Act." "The appeal of the State of U.P. above said was dismissed with cost." But there are decisions of Patna High Court which are in per in curium like one in Bhola Ram Choudhary & others v/s State of Bihar 1989 PLJR - 920 and others where it is held to be a Govt. Grant.

The deterioration in education, training and understanding of revenue laws by political Masters and state Amlas have created a mess of the system in the state govt. of Bihar along with lust of chief ministers. Once praised for the administration, the state apparatus have collapsed. Shree Lalu Prasad stayed the lease renewals in 1992 of Town Khas Mahal in Bihar and from then only handful of lease renewal orders were passed of influential person like High Court Judges, D.G.P.(S), I.A.S., I.F.S. officers etc. in Munger Town. As per D.O. Letter No. 70 dated 24-08-1998 of Collector Munger Dr. S.C. Mishra to Shri D.P. Maheshwari Secretary Revenue and Land Reforms, Bihar, Patna - 2621 Cases of Lease renewal were pending since 1992; As per R.T.I. query it was informed that 18 lease renewal case have been allowed till date in Munger Town-naturally only of influential people. The Amlas do

not receive rent from the occupiers of Khas Mahal properties on the instructions of D.M.(s) to create defaulters.

The Nitish Kumar Govt. of Bihar in 2011 in which Sushil Modi (B.J.P.) was Dy. C.M. and finance Minister brought a New Khas Mahal Policy 2011 and declared in definance of Hon'ble Supreme Court that Khas Mahal leases were under Govt. Grants Act, and declared that whosoever have not got renewed their lease are trespasser : Now at one hand the process of renewal of lease is the duty of the State Amlas - why they failed to renew the 2621 lease renewal applications is a matter between State and its "NIKAMMA AMLAS" in the name of breach of terms of agreement of lease - but Nitish Kumar indulged in backward - forward politics along with Sushil Kumar Modi Dy. C.M. in bringing New Khas Mahal Policy 2011 affecting Lakhs of home and losing creditibility. He lost the 2014 Parliamentary Election simply due to HATE - POLITICS. Narendra Modi cashed it because of his image of a politician who can perform under any pressure, to the glee of B.J.P. which was ousted from Nitish Govt. and thus escaped the public wrath.

The leadership of the State of Bihar has to understand that Town Khas Mahal is under T.P. Act and Right to transfer is incidental to

property. There cannot be absolute restraint in law from transferring it. Even more, law says that the STATE has only "Right to Rent".

It appears that the state Govern-ment had not, at any point of time had any Title to the possession of these Town Khas Mahal lands. If, as the Government contend, these lands were rent paying lands, the title of the State Government was simply to the rent.

The State Govt. never alleged nor proved its Title over the Town Khas Mahal Lands, if by any act or omission in the part of owners of the land working a forfeiture, the Govt. simply wants to arm its self with powers of dispossession of rayats / tenants unknown to Civil laws and Civil society of the country by inforcing New Khas Mahal Policy 2011 and its amendments and not renewing the 2621 Lease Renewal cases pending since 1992.

In this regard I suggest to go through the decision of Judicial Committee of the Privy Council in GUNGA GOBIND MUNDUL and others - AND - THE Collector of the Twenty four parganas and others in 1867. (Appear from the East Indias)

The Town Khas Mahal died on 26-11-1955 by Bihar Govt. Notification under Land Reforms Act 1950 and the Department of Khas Mahal's Departmental Head

called District Khas Mahal Officer vested in the Department of Land Reforms Under D.C.L.R. All tenants of even Town Khas Mahal holding land for over 12 years are now occupancy raiyats of the State of Bihar as there is no more Khas Mahal Deptt. in Bihar after abolishing Zamindari.

To understand the origin in-short of "Khas Mahal" one can understand that the ESTATE OF KHAS-MAHAL belonged to the Mughal Emperor himself.

permitted the British East India Company to acquire zamindari rights in different Khas Mahal villages i.e. the Company got the "Right to Rent", and nothing else.

From Company this "Right to rent" vested in the Secretary of state for India in council - after the administration of India was taken over from it by Statute of the British parliament in 1858 – first being Lord Stanley appointed as such on 02.08.1958.

there is no rule-making power vested to the State Govt. and which is a superior legislation covering the whole filed, the vested rights to the lesse/Tenants/ absolute proprietors can not be taken away except under authority of law. These rule making power of State Govt. without the support of a legislation / legislative enactment is not capable of achieving such an ends as Khas Mahal Policy 2011.

■

As, lease of Khas Mahal land is operating under T.P. Act, where



सरस्वती विद्या मंदिर SARASWATI VIDYA MANDIR बक्सर—आरा रोड, अहिरौली, बक्सर Buxar-Ara Road, Ahirauli, Buxar



Affiliation No :- 330460

E-mail :- svmbxr@gmail.com

School code :- 50410

Web Site :- www.svmbuxar.org

अन्य संचालित खण्ड

सरस्वती विद्या मंदिर (बालिका खण्ड)

सिविल लाइन्स, बड़ा बाजार, बक्सर

हमारी विशेषताएँ

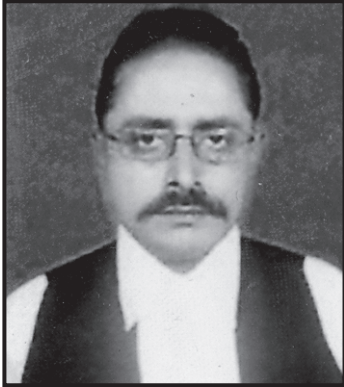
1. कक्षा प्रवेश से दशम तक की व्यवस्था
2. भारतीय जीवन— आदर्शों पर आधारित नगर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय
3. विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा मार्गदर्शित
4. आधुनिक उपकरणों से युक्त विज्ञान एवं संगणक प्रयोगशाला
5. स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था
6. कम्प्यूटरीकृत कार्यालय
7. योग विषय की अनिवार्य शिक्षण
8. आचार्यों के माध्यम से सघन अभिभावक सम्पर्क
9. पंचपदी शिक्षण व्यवस्था
10. योग्य एवं अनुभवी आचार्य
11. विशाल, सुसज्जित भवन एवं क्रीडांगन
12. भैया—बहनों के लिए वाहन सुविधा



मंत्री
हृदयानन्द सिंह

प्रधानाचार्य
धनंजय शर्मा

Gram Panchayat Raj



Shri Prakash Srivastava
Secretary General
Advocate Association
Patna High Court, Patna

The institution of the village Panchayat has a long history in our country. In Vaidic India, an autonomous village community was a special feature of the social fabric of the society.

The processes exercised by the Panchayats were both executive and judicial in the ancient India. Thereafter in our country foreign invaders came and due to their invasion and eavesdrop motive and motivated impetuous demeanour to our ancient culture and social fabric our glorious heritage was totally dismantled.

The concept of Panchayat Raj was not a new concept for our country. The local self-govt. & Panchayat Raj were effectively functioning in our country from ancient period. The human value always respected in our ancient India. But by lapse of time,

foreigners invaded in our country & accordingly their own culture & civilization remolded our governing system, which caused harm, not only to our culture but also our ancient rich heritage.

Mugal Empires were primarily concerned with cruelty, valuable movables of this country. Shersah Suri gave a new thought and concept for lands, its method for measurement under the leadership and control of Todarmal [resident of East Champaran]. Shersah Suri created a history through G.T. road. But in the Mughal dynasty save and except the period of Akbar and Jahangir, no positive contribution was made to maintain communal harmony of our ancient India.

The British rulers in their first attempt introduced and established the local self-govt. in the year 1882. The district fund committee was established by the Govt. of Bombay. The district fund committee was purely a nominated body. The Lord Rippon in the year 1882, established local self-govt. with the setting up District Local Boards.

The District Board and the District Council were established in the Marathwara and Vidarbha.

The Local Self Govt. was enacted by the British rulers in the year 1882. After the independence, the Bihar State was the pioneer state as immediately after the

independence, the Bihar Govt. introduced The Bihar Panchayat Raj Act, 1947. The reason behind promulgation of Bihar Panchayat Raj Act, 1947, was by dint of this fact that the public in general of our state were deeply associated with the Gandhian thought. In true sense Champaran was the land which enlightened Gandhi Jee to start stir and revolution against the British rule. Virtually Gandhi Jee visited in every part of our state, so the leaders of Bihar State, immediately after the independence and prior to introduction of our constitution introduced the Bihar Panchayat Raj Act, 1947.

Gram Panchayat Raj was the positive thought & thinking of grass-root democracy. The democracy and the democratic system is meant for direct participation of every citizen. In larger prospect and for direct participation of people at grass-root, BIHAR PANCHAYAT RAJ ACT 1947 was introduced.

Vaishali was the first school of democracy while Nalanda was the first & last school of literature. Our country has tremendous socio-economic graphics. Sabri, was respected by the Lord Rama while Lord Krishna respected Sudama. Lord Rama respected the sentiment of a washer man and axe Sita. Our old ancient culture never recognized caste creed & religion.

Our ancient culture always respected the merit education and research. But subsequently in later days deterioration developed due to foreign invasion, resulting thereto rampant deterioration, persued in our society, culture and socio-economic thought.

Our State, after independence, opted to develop local self govt. promulgated Bihar Panchayat Raj Act., 1947 (Bihar Act. 7 of 1948). Article 40 of the constitution of India deals with to organize village Panchayats & endow them with such powers & authority, as may be necessary to enable them to function as units of self-government. Although, this Article does not lay down the directive to rule whole country through Panchayats & Panchayats alone. Previously, original Part IX consisting of Article 243 was repealed by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, which was inserted by Constitution 73rd Amendment Act, 1992. The Constitutional 73rd Amendment Act, 1992, created a positive hope for development of grass-root democracy. Eleventh schedule of the Constitution, created new dimension for administration through Panchayats. The Bihar Panchayat Raj Act, 1947 (Bihar Act 7, 1948) was promulgated in order to develop the local self-government (The Bihar Panchayat Raj Act was consented to) by the Governor General on 12 February, 1948 and was notified in Bihar Gazette on 3rd of March, 1948.

Previously, in the Bihar Panchayat Raj Act, 1947, the

eligibility for being a voter was twenty one year, which was subsequently amended by the Bihar Act 7, 1990. By the amendment in Bihar Panchayat Raj Act, 1947, by adding section 2(a) the eligibility criteria for being a voter was reduced upto the age of 18 years.

In the Bihar Panchayat Raj Act, 1947, the power conferred to the State Government to establish and constitute PUNCHAYAT. In section, 3 of old Act (Bihar Act 7, 1948) there was conferment of constitution, addition and exclusion of area of Panchayat. The State Govt. introduced The Bihar Gram Panchayat Act 1990, accordingly new amendment were made considering the need of our State. Section 3(k) and section 3(k-a), by amending the Bihar Panchayat Raj Act, 1948, was inserted resulting thereof an Election Commission was constituted. 3(k-a) to 3(t-a) gave a new dimension to the Panchayat & Panchayat Raj system.

For strengthening the democracy at grass root level and the well noted thought of abraham Lincon, that the "democracy is the Government of the people, for the people and by the people" Part IX of the constitution was incorporated. Part IX of the constitution was inserted by the constitution (73rd Amendment) Act, 1992. The original Part IX, consisting of Article 243 was repealed in the year 1956. The part IX of the constitution (73rd Amendment) Act, 1992 came into force on 24.04.1993. Article 243B of the constitution deals with

constitution of PANCHAYAT. While Article 243C deals with the composition of three tier, Panchayat namely PANCHAYAT RAJ, PANCHAYAT SAMITI and ZILAPARISHAD.

The Panchayats have got, now, constitutional protection. The amendment in constitution was made for establishing Panchayat at village level, intermediate level and the District level. The most important fact of our Panchayat Raj system is that, it can't be suspended or superceded for long. as a mandatory embargo, fresh election would have to be held within six months of its dissolution. The corollary of our Panchayat Raj, that seats have been reserved for woman (most neglected class of our society) M.B.C. (most oppressed class of our society) and for the people of SC and ST. The term & tenure of Panchayat have been fixed for five years. The Panchayat have been conferred power to prepare their own budget, collect revenue, impose taxes & to prepare development plans. The Panchayat shall be able to prepare their own development schemes and to implement these schemes effectively. District Planning Committee, Finance Commission & the Election Commission for Panchayats have been constituted.

The constitution (73rd Amendment) Act, 1992, and the constitution (74th Amendment) Act, 1992, was added as new Part IX of the constitution. These apart a new schedule XI was also added in our constitution.

The constitutional (73rd

Amendment) Act. 1992, reflected a hope for the people of our country, that a new era will begin in order to nourish and develop grass-root democracy.

Thereafter the State Govt. after repealing the Bihar Panchayat Raj Act 1993 promulgated a new Act under the name and style of THE BIHAR PANCHAYAT RAJ ACT 2006. The Bihar Gram Panchayat Raj Act 2006 gave a new opportunity for representation for the Women to the extent of 50% reservation. Likewise 50% reservation to the Women, reserved 20% seats in the Panchayats for the MBC. That apart Gram Katchahry in every Panchayats has been established. The Sarpanch and Punch have been authorized to discharge the legal duties to adjudicate Civil and Criminal litigations. So the new Act

extended a positive hope for the people of unrepresented class and society. Undoubtedly, the reservation of seats in Panchayat introduced a new horizon for the people belonging to the unrepresented class of the society. In other words, policy of reservation, created a hope for the people of the society, who were not allowed even to vote as per their own wish. In our State due to unwarranted interference by the Administrative Agency under Sections 18(5), 44(5), 70(6) & 151 of the Bihar panchayat Raj Act., 2006, to control the three tier Panchayat in most devastating manner. Not only this much that despite of the introduction of "Lok Prahari" as mandated under Section 152(5), no notification has been made by the State Government. The basic reason for

failure to implementing the development schemes the State Government has not made any attempt to create a separate cadre of employees at the Panchayat level and due to this failure, the three tier Panchayats are not in a position to implement development schemes as per their own wish and desire, resulting thereof, the three tier Panchayats are not in a position to implement the development schemes to fulfill the hope of the people of State.

But, considering the overall aspect of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, I would like to suggest the failure in implementing the development schemes, in true letter and spirit to create a separate cadre of employees in order to discharge the duties in implementing the development schemes. ■



IjLorh f'k'kq eafnj

jk"V^ah; mPp iFk] vkSjaxkckn] fcgkj

lh0ch0,I0bZ0 ls lEc) ,oa

,u0vkbZ0vks0,I0 dk ekU;rk izklr v/;;u dsUnz



Affiliation No. 330074

School code: 9507

gekjh fo'ks"krk,i

- ⌚ Hkkjrh; thou vkn'kksZa ij vk/kkfjr mRd`"V fo|ky;
- ⌚ fo'kky] lqlfTtr Hkou ,oa ØhM+kaxu
- ⌚ ;ksX; ,oa vuqHkoh vkpk;Z
- ⌚ ek/;fed d{k kvksa dk mÙke ijh{k kQy
- ⌚ vk/kqfud midj.kksa ls ;qDr foKku ,oa lax.kd iz;ksx'kkyk
- ⌚ HkS;k&cguksa ds fy, okgu lqfo/kk
- ⌚ dEl;wVj] laxhr ,oa ;ksx fo"k; dk vfuok;Z f'k{k.k
- ⌚ vf[ky Hkkjrh; Lrj rd foKku] ;ksx ,oa a [ksy&dwn izfr;ksfxrkvksa esa Js"B
- ⌚ izn'kZu o ifj.kkeA
- ⌚ bZ0 Dyklst dh lqfo/kk



izHkkq

o p f l

jk"V

Z ; k p k u k k / z i

The Hindu Marriage Act 1755

MARRIAGE A SACRAMENT

In Hindu Law Marriage as treated as a Sanskar or a Sacrament



शिखा सिंह

अधिवक्ता

उच्च न्यायालय, पटना

विवाह एक संस्कार है संविदा नहीं। वेद वर्णित सोलह संस्कारों में अष्टम् (आठवाँ) है पाणिग्रहण संस्कार (विवाह संस्कार)।

आज की हॉल और लॉन की शादियों के समारोह से संस्कार पद्धति की विलुपता, इसे संविदा के तरफ परिणत करते जा रहा है।

जिसके विध्वंशकारी परिणामों से हम प्रोफेशनली प्रतिदिन रू-ब-रू होते हैं। व्यवहारिक मान्यता में प्रोफेसर और वकील बुद्धिजीवी नागरिकों की संख्या में क्रमशः प्रथम और द्वितीय आते हैं। सो कुछ युनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने भी दुष्परिणामों के अंदेशा से वर्तमान विकृतियों पर प्रकाश डालने हेतु कलम डटा लिये हैं—यानि आर्टिकलास के माध्यम से जागृति लाने की

सेवा कार्यों में उनके दायित्व निर्वहन का प्रयास दिख रहा है।

प्रकृति को साक्षी मानकर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से सिंचित एक-एक रस्मों-रिवाज अंशतः नहीं पूर्णतः विज्ञान है।

सुपर साइंस प्रुफ होनेवाला है हमारा 'कस्टम' सिस्टम।

उदाहरणस्वरूप—

1. शुद्ध हल्दी (सुपर एंटी एलरजिक) का मिश्रित उपटन का लगभग सारे शरीर में मसाज।
2. 'उपवास' (जिसे 'रोजा और पर्व-व्रत पर रिसर्च' भी मौसम और काल अवधि की चिकित्सा पद्धति ही ट्रीट किया है यानि उक्त सप्ताह, पक्ष के सुनियोजित यौवन और उपवास की रस्में।
3. मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पर आधारित वर का कन्या पक्ष के महिला मंडली द्वारा औचक प्रश्नोत्तरी, प्रति-उत्तर क्षमता का स्तर जाँच।

प्रथम दृष्ट्या में शारीरिक दृष्टि आँकलन की भी सार्वजनिक पुष्टि हेतु मंडप में वैवाहिक वैदिक वस्त्र धारण करने से लेकर मंडप परिक्रमा, उखल-मुसल का प्रयोग

जैसे रस्म आदि आदि। ठीक उसी तरह कन्या का बहु की स्वागत डाली में लम्बा चलना, कौड़ी-क्रीड़ा, प्रार्थना स्थली (पूजा-घर) रसोई-भंडार कक्ष आदि में 'स्पर्श एवं वितरण' रिवाज।

पटना विश्वविद्यालय के एक व्याख्याता ने 'कोहबर कक्ष' में दिवाल पर बनने वाले आकृतियों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव कीड को महत्वपूर्ण बताते हैं। उनके लेख में अंकित वाक्य महात्मा बुद्ध ने भी रानी यशोधरा को अपने शौर्य पराक्रम आदि से 'कोहबर कक्ष' में ही अवगत कराया था।

हॉल-लॉन में फंक्सन के आडंबरों में फंसकर उच्च वर्ग, मध्य वर्ग से निम्न वर्ग तक सभी इसकी अवहेलना, अनदेखी एवं अन उपयोगी प्रमाणित करने में आधुनिकता का गौरव महसुसते हैं।

अतः इस गंभीर चिन्तन के प्रति पादकों का ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा ही इस असामान्य लेख का पहल है।

द्वितीय अंक आगे भी लिखने का प्रयास जारी रखना ही अपना संकल्प है।

क्यों हम स्त्री सम्मान की सुरक्षा में इतने बड़े-बड़े सेमिनार डिवेत्स आदि "कार्यक्रमों की प्राथमिकता" विमेन्स

प्रोटेक्सन लॉ एंड रिफार्मस के शोध को विवाह पर आधारित नहीं कर पाते।

दामपत्य-शुभ की प्रामाणिकता संतान जन्म संस्कारों के रास्ते भी मानवीय मौलिकता को सुव्यवस्थित करने एवं आदर्श नागरिक को निर्माणशील राष्ट्र के दम पर

हम अपने गौरवशाली स्वर्णिम भारत को वापस अनुभव कर सकते हैं। 'मानव निर्माण से राष्ट्र उत्थान' जिसके लिए भविष्यद्रष्टा स्वामी विवेकानन्द के शब्दों से लेख की समाप्ति करना श्रेष्ठकर होगा—

वह देखो, भारत माता धीरे-धीरे आँखें

खोल रही हैं। वो अभी थोड़ा ही सो पाई हैं उठें, उन्हें जगाएँ, आदर भाव से पहले की अपेक्षा और भी गौरव मंडित करके अपने उनके निरंतर सिंहासन पर प्रति स्थापित कर दें। ■

School Code : 50113

Affiliation No. : 330198



ANANDRAM DHANDHANIA SARASWATI VIDYA MANDIR



(Affiliated to CBSE, New Delhi upto Senior Secondary Level)

BUDHANATH ROAD, BHAGALPUR

(0641-2302901, Fax - 0641-2301719, E-mail : bgp_prardvsm@rediffmail.com)

**A Unique 10+2 School with a Difference based on
CBSE curriculum and Indian Culture**

Salient Features

- ★ Well Furnished Library with Maths Laboratories
- ★ Audio-Visual Facilities.
- ★ Well Furnished Computer Labs with Internet Facilities
- ★ Smart (Digital) Classes
- ★ Scout & Guide Training
- ★ Co-Educational and Healthy Natural Surroundings



Special Classes for Medical, IIT, C.A., Maths and Science Olympiad

**Admission Form and Prospectus can be had from the school counter
on working days from 10.00 A.M. to 04.00 P.M.**

Chhedi Lal Choubey
(President)

Manoj Kr. Mishra
(Principal)

Naresh Kr. Khetan
(Secretary)

IMPACT OF ANNUAL INFORMATION RETURN ON COMMON TAX PAYER ASSESSEES UNDER THE INCOME TAX LAW



R.K. Mishra
Advocate
Ranchi

What is Annual Information Return (AIR)?

As per section 285BA of the Income Tax Act, 1961, read with Rule 114E of the Income Tax Rules, 1962, specified entities (Filers) are required to furnish an Annual Information Return (AIR) in respect of specified financial transactions registered/recorded by them during the financial year (beginning on or after April 1, 2004) to the income tax authority or such other prescribed authority.

Who is required to furnish AIR?

The AIR is required to be furnished by specified persons in respect of specified transactions registered or recorded by them during a financial year as elaborated in the following table :

Sl. No.	Class of Person required to Furnish AIR	Nature of Transaction	Amount of Transaction during financial year
1.	Banking Company	Cash Deposit in savings Bank A/c	Rs. 10 Lacs or more
2.	Any company or institution issuing credit card	Payments made in respect of a credit card	Rs. 2 Lacs or more
3.	Trustee or authorized manager or Mutual Fund	Receipt from any person for acquiring units of that Fund	Rs. 2 Lacs or more
4.	Company or institution issuing bonds or debentures	Receipt from any person for acquiring bonds/debentures	Rs. 5 Lacs or more
5.	Company issuing shares through a public or rights issue	Receipt from any person for acquiring shares	Rs. 1 Lac or more
6.	Registrar or Sub-Registrar	Purchase/sale of immovable property by any person	Rs. 30 Lacs or more
7.	Authorized officer of the	Receipt from any person	Rs. 5 lacs or more

In other words, the IT Department has complete knowledge of your high value transactions relating to seven categories, namely :

1. If you have deposited Rs. 10 lacs or more in a Savings Bank account held with any bank.
2. If you have expended Rs. 2 lacs or more from your credit card.
3. If you have purchased Mutual Fund of a particular company for Rs. 2 lacs or more.
4. If you have purchased Bonds/debentures of a particular company for Rs. 5 lacs or more.
5. If you have purchased Shares of

a particular company for Rs. 1 lac or more by IPO or right issue.

6. If you have purchased or sold any immovable property for Rs. 30 lacs or more.
7. If you have purchased Bonds of RBI for Rs. 5 lacs or more.

almost 23 crore of such high-value transactions are under the scanner of IT department and enquiry letters/notices have already been dispatched to thousands of taxpayers. The enquiry letter/notice typically asks the taxpayer to respond in writing. His personal presence is not required. Accordingly cases are selected for

scrutiny if proper reply is not received from the tax payer.

Scope of enquiry in the scrutiny cases selected on the basis of information collected from AIR returns :

It is very important to know the scope of enquiry which can be made once a case is selected for scrutiny due to AIR. As per notification F. No. 224/26/2006-ITA.II (Pt.) dated 8th September 2010 scope of enquiry in the scrutiny cases selected on the basis

of information collected from AIR returns would be limited to the aspects of information received through AIR.

However a case may be taken for wider scrutiny with approval of administrative commissioner if it is felt that the income escaped is more than Rs. 10 Lakhs.

But in practice all such cases are dealt in as regular scrutiny calling for all detailed information from the tax payers resulting in undue hardship.

Conclusion & Suggestion :

The common tax payers, business men and even professionals are suggested not to play blind games especially in transactions relating to real estate and property dealings as well as not to route regular/frequent business cash transactions in your savings bank account (rather can open a separate Current A/c) and to be conscious in all the above mentioned categories while planning your high value financial transactions.

आगत प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत !

मेसर्स नारायणी प्रिन्टर्स

पटेल नगर, पटना-23

ऑफसेट एवं वेभ क्वालिटी प्रिन्टींग

श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा

प्रबंधक

मो.नं.-9334135334



अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय परिषद का त्रिदिवसीय बैठक जो दिनांक 27, 28 एवं 29 दिसम्बर 2014 को पटना में होना निश्चित है, उक्त अवसर पर प्रदेश इकाई का स्मारिका का प्रकाशन सराहनीय है।

वर्णित बैठक में देश के समस्त अपेक्षित राज्यों से भाग लेने वाले परिषद सदस्य को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं।

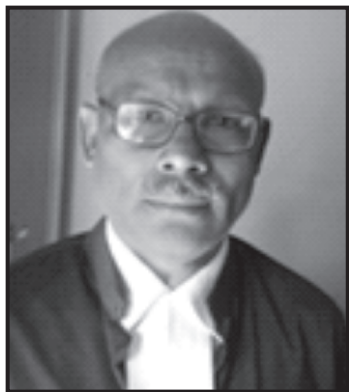
शुभेच्छु

सामाजिक युवा कार्यकर्ता

संजय कुमार मिर्धा

कसबा, पूर्णियाँ, बिहार

हमारे प्रेरणास्रोत दत्तोपंत ठेंगड़ी



राकेश चन्द्र वर्मा

अधिवक्ता
सिविल कोर्ट, मुंगेर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, विचारक तथा चिंतक दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म दीपावली (कार्तिक अमावस्या) संवत् 1977, विक्रम तदनुसार 10 नवम्बर 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जनपद के अन्तर्गत आरवी नामक स्थान में हुआ था। वे 15 वर्ष की किशोरावस्था में सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किये थे। उनकी शिक्षा एम.ए.एल.एल.बी. तक थी। वे अध्ययन काल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्मठ, निष्ठावान एवं सक्रीय स्वयंसेवक थे तथा 1942 में संघ के प्रचारक बने। रा. स्व. संघ के सरसंचालक परम पूज्य माधव राव सदाशिव गोलवलकर उर्फ श्री गुरुजी से ठेंगड़ी जी का निकटतम सम्बन्ध था और वे गुरुजी के सानिध्य में संघ का कार्य व विस्तार करने में अपनी अहम भूमिका प्रदान किये।

केरल, पश्चिम बंगाल आदि में

राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्य का सुदृढ़ आधार खड़ा करने में ठेंगड़ी जी का विशेष योगदान रहा। वे भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सामाजिक समरसता मंच, पर्यावरण मंच, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मंच, भारतीय विचार केन्द्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि के संस्थापक सदस्य (Founder Member) रहे, इसके अलावे इनके मार्गदर्शन प्रेरणा एवं विचार से अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् की स्थापना 7 सितम्बर 1992 को हुई जिसका ध्येय वाक्य रखा गया – “न्याय मम् धर्मः” अर्थात् न्याय ही हमारा धर्म है। इसलिए अधिवक्ता को न्यायिक क्षेत्र में न्याय का स्तंभ कहा गया है। (Advocates are pillar of justice). ठेंगड़ी जी के प्रेरणा से भारतवर्ष के कई प्रान्त, जिला व नगर में अधिवक्ता परिषद् की स्थापना हो गई है और परिषद् अपने मंच से प्रत्येक वर्ष विचार गोष्ठी आदि कर समाज को एक नई दिशा न्याय के क्षेत्र में प्रदान कर रहा है। यह मंच राष्ट्र के एकता, अखंडता और प्रभुता के लिए समर्पित है तथा नृबल वर्ग को विधिज्ञ सहायता उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग कर रहा है।

अधिवक्ता परिषद् एक गैर-राजनैतिक संगठन है और इस संगठन के सदस्य ठेंगड़ी जी के प्रेरणा से सामाजिक समरसता व न्याय के हित में कानून का विश्लेषण कर राष्ट्र हित में अपना विचार

प्रकट कर रहे हैं।

भारतीय मजदूर संघ को भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विशाल संगठन बनाने का श्रेय हमारे ठेंगड़ी जी को जाता है, उन्होंने भारतीय मजदूर संघ को एक ठोस आधार दिया, जिसके लिए भारीय मजदूर संघ ठेंगड़ी जी के नाम से आज भी जाना जाता है। ठेंगड़ी जी ने अपने भारतीय विचार को प्रदर्शित करने के लिए विश्व के अनेक देश चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा भ्रमण कर भारतीय व विश्व मानस का गंभीर सूक्ष्म अध्ययन कर तथा कम्यूनिस्ट चीन के श्रमिक जगत का मार्गदर्शन किया।

हमारे ठेंगड़ी जी 1964 से 1976 तक राज्य सभा के सदस्य रहे और 1968 से 1970 तक राज्य सभा के उप-सभापति भी बने। वे भारत सरकार द्वारा संसदीय कार्य हेतु रूस तथा हंगरी भी गए थे। उन्हें भारत सरकार पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करना चाहती थी किन्तु ठेंगड़ी जी ने यह सम्मान प्राप्त करना स्वीकार नहीं किया। वे देश की सेवा निःस्वार्थ भाव से करते थे और अपने स्वार्थ में किसी भी प्रकार का मूल्य लेना पसंद नहीं करते थे।

हमारे ठेंगड़ी जी में अध्ययन की व्यापकता, चिंतन की गंभीरता, विश्लेषण की गहनता एवं सूक्ष्मता, ध्येय को प्रतिपूर्ण तादात्म्य तथा तन्म्यता, बाल सुलभ

निष्कपटता, रहन-सहन की सरलता तथा उज्ज्वल भारत की भविष्यता का गहन विश्वास था। ठेंगड़ी जी को राष्ट्र ऋषि भी कहा जाता था, वे सखोनमुखी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सैकड़ों पुस्तक-पुस्तिकाओं का प्रणयन किया। संस्कृत, हिन्दी, बंगाली, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था तथा सामाजिक विषयों पर वे

धाराप्रवाह बौद्धिक विचार देते थे और लक्ष्यबद्ध देशवासियों के प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक थे।

पूज्य ठेंगड़ी जी जीवन के अंतिम क्षण तक संघ कार्य करते हुए विविध क्षेत्रों में अपनी भारतीय विचार देते हुए 14 अक्टूबर 2004 को ब्रह्मलीन हो गए। वे आज भी अधिवक्ता परिषद के लिए प्रेरणा पुरुष हैं।

उनका स्मरण कर प्रत्येक वर्ष अधिवक्ता परिषद को उनकी पुण्य तिथि मनानी चाहिए। ऐसे महापुरुषों को जिला अधिवक्ता परिषद एवं संघ परिवार शत-शत नमन करता है, जिनके प्रेरणा से आज अधिवक्ता परिषद अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

“मातृछाया”
लालदरवाजा, मुंगेर

With Best Compliments from :

Sanjay Kumar

Mob.- 9334023585
9304809784



SHYAM PUSTAK BHANDAR

H.O.: Akashwani Road, Khajpura, Bailey Road, Patna-14

B.O. : PATNA/BUXAR

E_mail-shyampustakbhandar161@gmail.com

Ph.:9304870318 (Office)



अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय परिषद बैठक में जो दिनांक 27, 28 एवं 29 दिसम्बर 2014 को पटना में होना निश्चित है, के उपलक्ष्य पर स्मारिका का प्रकाशन सराहनीय है।

वर्णित कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से अपेक्षित भाग लेने वाले समस्त परिषद सदस्य बंधु को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं।

शुभेच्छु

विजय कुमार खेमका
गुलाब बाग, पूर्णियाँ, बिहार
समाजसेवी

भारत की शिक्षा नीति एवं अधिवक्ताओं की भूमिका



डॉ० प्रेमनाथ पाण्डेय

संयोजक

शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति, बिहार

1996 में यूनेस्को ने शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए समूचे विश्व के शिक्षाविदों को अपने यहाँ बुलाया था। इस बैठक में भाग लेने के लिए भारत से प्रख्यात शिक्षाविद् डा० कर्ण सिंह भी गए थे। वहाँ गठित डेलर्स कमिटी ने अपने रपट में कहा कि किसी भी देश की शिक्षा नीति उस देश के संस्कृति के अनुरूप विकासात्मक होनी चाहिए। उक्त पहलू पर विचार करें तो इस प्राचीन देश में पूर्व से ही उक्त विचार के आधार पर शिक्षा पद्धति चल रही थी, बल्कि उससे भी आगे। अपने देश के बालकों को अपने देश की संस्कृति, प्रकृति एवं मानव मन के प्रवृत्ति के आधार पर गुरुकुलों में दी जाती थी। नामांकन के समय ही बालकों का काउंसिलिंग हो जाया करता था। समाज के सभी वर्ग के लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा सरकारों की चेरी नहीं अपितु समाज की धरोहर थी। फलतः इस देश में कोई भी

अशिक्षित नहीं था।

The beautiful tree के शोधपरक लेख के लेखक प्रख्यात गाँधीवादी महाशय धर्मपाल ने भी इस की पुष्टि की है। परंपरागत शिल्प, कृषि, विज्ञान की इतनी अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था थी की गुरुकुलों से निकलने वाले छात्र नौकरी नहीं खोजते थे, अपितु स्वालंबन के आधार पर समाज की सेवा करते थे। यही कारण था कि इस्लामी आक्रमण के बावजूद अपना देश विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया था। घरों में ताले नहीं लगते थे, कोई भूखा नंगा नहीं था। मेगास्थनीज, फाह्यान एवं ह्वेनसांग ने भी ऐसा ही भारत देखा था। जब अंग्रेजों का शासन भारत पर स्थापित हो गया तो उन्होंने इस देश की शिक्षा नीति बदल डाला।

इतने विशाल देश पर शासन करने के लिए उन्हें आंग्ल भाषा में शिक्षित कुलीन वर्गों से कलर्क चाहिए था, चाहिए था कानूनगों एवं कलक्टर। जमींदार जो उनका पक्ष ले सके। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विफलता के बाद 1861 में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। उस के पूर्व बंगाल प्रांत के (आज का बंगाल बिहार, उड़ीसा) सभी टोलों में विद्यालय थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में तो कोई अनपढ़ था ही नहीं। ब्रिटेन में भी मद्रास की तर्ज पर 1840 में मद्रास सिस्टम ऑफ एजुकेशन लागू किया गया और वहाँ सत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त की गई। उसके पूर्व वहाँ महिलाओं की शिक्षा की कोई व्यवस्था

नहीं थी। भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए आधुनिक शिक्षा के नाम पर भारतीय भाषाओं खास कर संस्कृत को सिरे से नकारने का प्रयास किया गया। भारतीय भाषाओं का अपमान करते हुए आंग्ल भाषा के शिक्षा के लिए ही फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। सबसे पहले महात्मा गाँधी का ध्यान इस ओर गया। उन्होंने नवजीवन में लिखा कि “अंग्रेजों ने शिक्षा और कला के क्षेत्रों की भारतीय व्यवस्था को स्वीकार कर और उस में आवश्यक संशोधन कर इसे विकसित करने के स्थान पर उसे नष्ट करने की नीति अपनाई”। तत्कालीन समाज द्वारा संचालित विद्यालयों से उनके अपने उद्देश्यों की पूर्ति न होने से उन्होंने उस के स्थान पर एक केंद्रीय कृत व्यवस्था लागू की, जिसमें शालाओं को अच्छा भवन, सुंदर फर्नीचर एवं ब्लैक बोर्ड आदि अनिवार्य कर दी। पूर्व में ऐसी शालाएँ नहीं थी। सार्वजनिक मंदिरों में बैठकर सभी शिक्षा प्राप्त करते थे। पूज्य बापू ने कहा था कि इस शिक्षा नीति से भारत की शिक्षा बहुत मँहगी हो जाएगी। सचमुच आज भारत की शिक्षा बहुत मँहगी हो रही है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है और पब्लिक स्कूल सामान्य आदमी की पहुँच से बहुत दूर हो गया। आजादी के पूर्व शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए अनेक आयोग बनाए गए और आजादी के बाद भी कई आयोगों का गठन किया गया। पर सरकार की नियत में खोट होने के कारण सभी रपटें धूल फाँक रही है। वर्तमान

शिक्षा नीति से राष्ट्रभक्ति से विमुख सांस्कृतिक रूप से मूल्य विहिन एवं शारीरिक रूप से लुंज-पूज एवं ललबबुआ पैदा हो रहे हैं जो स्वार्थी एवं असामाजिक होते जा रहे हैं। माता-पिता एवं आचार्य के सरोकार से वे कोसों दूर हैं। यह एक चुनौती है। सरकार ने भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अक्टूबर 2008 एवं शिक्षा का अधिकार 2009 लागू कर इसे ठीक करने

का प्रयास किया है। भारत की शिक्षा नीति को पटरी पर लाने के लिए बालकों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही करनी होगी। जीवन मूल्यों की शिक्षा अनिवार्य रूप से उन्हें देना होगा। पंचकोषीय शिक्षा के माध्यम से अर्थात् शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक तथा नैतिक एवं अध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास करना होगा तथा उन्हें

मानव से महामानव बनाने के लिए व्यक्ति से परमेष्टि की यात्रा सुनिश्चित करानी पड़ेगी। यानी स्वार्थी बालक के स्व का विकास करते हुए उसे परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व सृष्टि से होते हुए प्रवेष्टि तक पहुँचाना होगा। अधिवक्तागण शिक्षा के इस पुनीत लक्ष्य को प्राप्त करवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ■

आगत प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत !



“बिहार प्रदेश का मशहूर मनेर लड्डू”

मेसर्स मनेर स्वीट्स

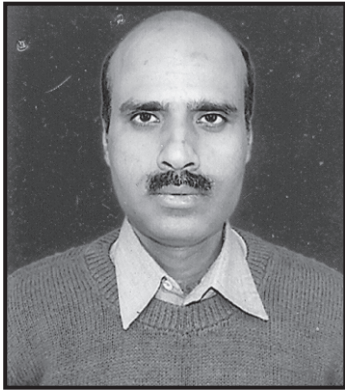


खेदलपुरा (बिहटा) आरा-पटना रोड



मौर्या कम्प्लेक्स, कोतवाली, पटना

Erosion of Values in Judicial System and its Refurbishment



Lakmesh Marvind
Advocate
High Court, Patna

“To punish the wicked ,
to honour [protect] the good ,
to enrich the treasury
(exchequer) by just methods ,
to be impartial in
rendering justice to the
litigants , and

to protect the Kingdom
– these are the five Yajnas (selfless duties) to be performed by a King [Judge]”
{ Atrisamhita -28 }

In our country erosion of values in dispensation of justice is not unknown to a common man of the society . Being myself an Advocate , I remorse and apologies to the people of our fraternity submitting that the moral and ethical values of our friends have significantly deteriorated

to such an extent that today this topic has gained momentum and which needs its refurbishment .

In an infamous BMW hit and run case a sting operation revealed a senior advocate, Supreme Court Of India and former Member of Parliament in collusion with Special Public Prosecutor allegedly offering money to the controversial witness to depose in favour of the prime accused in the case . In this case Hon'ble Supreme Court upheld the conviction of an eminent criminal lawyer for contempt of court in the BMW hit and run expose . The apex court found Special Public Prosecutor's conduct inappropriate but set aside his conviction and cleared him of contempt charges . There are many examples which are not enumerated and highlighted and therefore they have not come into the knowledge of the people of India .

Advocates, in addition to being professionals, are also officers of the courts and play a vital role in the administration of justice. The set of rules that govern their

professional conduct arise out of the duty that they owe the court, the client, their opponents and other advocates.

The role of Advocates starts when criminal cases are instituted by filing FIR , fardbayan , or a complaint case and ends when it is decided . Absence of witnesses in the criminal cases even after repeated issuance of summons and warrants; driving out of the witnesses of the criminal case by the defense side in a collusive venture and connivance; absence of prosecutor and defense lawyer; non-production of accused persons by the jail authority are the key component hindering speedy disposal of cases. Failure of producing the accused persons by the jail authority outside the districts on grounds of their involvement and being wanted in other criminal cases of the said districts for shortage of police escorts; ascendance of the accused persons and their voluntary surrender before the court in the middle of trial seeking for recalling of the witnesses

already examined which cause the delay. Splitting up of the criminal records for simultaneous trial of the adult as well as juvenile offenders at two separate court; frequent hearing to the bail matters for the same accused persons; non-appearance of the magistrate recording the confessional statements of the accused persons even after repeated issuance of summons and processes; non-arrival of the Investigation officer even after exhaustion of all the process; non-compliance of warrants by the police personnel; non-appearance of the expert witnesses for proof of the expert reports and dilatory tactics of the defense lawyer etc are the usual components of delay in the disposal of criminal cases. These are the common causes of delay, which are generally faced by the Judges during the trial of criminal cases. The criminal cases therefore right from the investigation by the police to the trial in the court delayed for favouring the guilty, a witness turns hostile either due to threat, coercion, lures and monetary considerations. And the result can be imagined. The victims / witnesses feel cheated and denied the protection of laws.

The Civil suit starts by

filing of the Complaint. Though the time is now fixed for filing the written statement however service of summons and the trial of the case consumes much time to the detriment of the litigants. No time is fixed for conclusion of the trial. The civil courts are expensive. Many cases cost more than is being claimed. There is a fertile field in the Code for a clever lawyer to prolong and protract proceedings to any length of time.

Therefore, there must be strong and transparent watchdog mechanism to ensure accountability of the advocates. It will result into the effective administration of justice. The provisions of professional misconduct of the advocates should be scrutinized and made effective in consonance with time and necessity.

In this way the conduct of the lawyers and courts in delivering effective, fair and impartial justice have eroded the values of the judicial system. The aforesaid delay in delivering judgments in criminal as well as civil cases and the allegation that the Judges acted under the influence of senior officials or politicians or money power shall be minutely scrutinized to strengthen the

administration of justice. The judges of criminal and civil courts must be thoroughly trained to dispense justice in their respective fields which must be demarcated. The judge who is trained to deal criminal cases must not be given to deal civil cases during his entire career of service, i.e. from the date of appointment to the date of their superannuation, and, the vice versa. This system must prevail from the court of Munsif to the judges of the Hon'ble Supreme Court.

The higher judiciary is highly dilatory, expensive and beyond the reach of common man. The appointment of the Judges of the higher judiciary is also not fair and transparent. A retired judge of the Andhra Pradesh High Court has published a booklet which title is "A caste captures Andhra Pradesh Judiciary" and has given figures how pedigree of the judges and the caste concern has effected the judges who are supposed to select judges for appointment in the vacancies that arise in future. In my opinion if the survey is conducted in all the States of India the facts and truth shall not be otherwise. A lawyer who becomes a Judge through corrupt means cannot be an honest Judge who could

deliver justice fairly and impartially .

It is need of the hour that the judiciary shall deliver judgments fairly , fearlessly and impartially and for which its proceedings will be televised for bringing transparency in the judicial system . Telecast shall impede the candour with which judges

address lawyers and litigants . There will be no adverse effect of telecasting court proceedings / trails . In many countries e.g. South Africa, U.S.A. etc. the court proceedings are telecast live and civil society plays a role in monitoring judicial decisions and performance . We Indians have also the right to know and

understand the courts and advocates beyond the judgments and manufactured news reports.

I now end my words by submitting that Bar and Bench are two arms of the same machinery and unless they work harmoniously and honestly justice can not be properly administered . ■

[Sch. Code-8207]

[Affiliated to C.B.S.E.]



सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

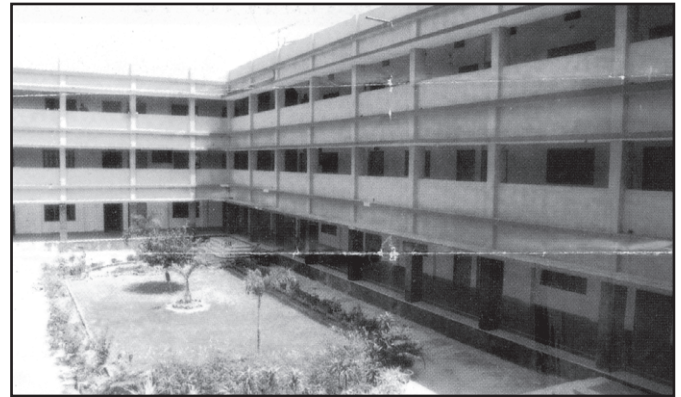
SARASWATI VIDYA MANDIR MUNGER

Senior Secondary School

E-mail : svm_mgr@yahoo.com, Fax : 06344-226417

हमारी विशेषताएँ

- ★ भारतीय जीवन आदर्शों पर आधारित उत्कृष्ट विद्यालय।
- ★ विशाल, सुसज्जित भवन एवं क्रीड़ांगण।
- ★ योग्य एवं अनुभवी आचार्य।
- ★ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं का उत्तम परीक्षाफल।
- ★ आधुनिक उपकरणों से युक्त विज्ञान प्रयोगशाला एवं Wi-Fi Networking and Broadband
- ★ Internet से युक्त संगणक प्रयोगशाला।
- ★ भैया-बहनों के लिए वाहन सुविधा।
- ★ कम्प्यूटर एवं योग विषय का अनिवार्य शिक्षण।
- ★ अखिल भारतीय स्तर तक विज्ञान, योग एवं खेल-कूद प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन व परिणाम।
- ★ NIOS बोर्ड (HRD, Govt. of India) से मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्तर तक का अध्ययन केन्द्र।
- ★ E-Classes Facilities.



प्रो० विरेन्द्र पोद्दार
अध्यक्ष

निर्मल कुमार जालान
सचिव

अमरेश कुमार
प्रधानाचार्य

अनैतिक मानव व्यापार प्रतिबंध कानून (ITPA) और इसकी चोट



डॉ० शोभा चौबे

अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय

‘अनैतिक मानव व्यापार प्रतिबंध कानून’ को लागू हुए 6 दशक होने को है बीच में इसमें संशोधन भी हुये पर अभी तक मानव व्यापार में सुधार की बजाय भयानक बढ़ोतरी दर्ज किया जाना वाकई चिंताजनक है। इस दिशा में कई-कड़े कदम भी मानव द्वारा मानव का व्यापार पर रोक लगाने में ना काफी रहे।

दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी कानून अपने नागरिकों की भलाई के लिए बनाया जाता है जिसमें वो भेदभाव रहित मुक्त एवं गरिमापूर्ण वातावरण में अपने अधिकारों के साथ अपना सर्वांगीण विकास कर सके। यह कानून दोषियों को सजा और पीड़ितों के पुनर्वास की बात करता है परन्तु इसकी कुछ धाराएँ पीड़ितों के विरुद्ध चली जा रही हैं। वेश्यावृत्ति

अच्छा पेशा है या बुरा, इसमें लगे लोग अपनी मर्जी से कहाँ है जबरदस्ती लाये गये हैं, ये अलग मुद्दा है। सच्चाई है कि आज वो इसी पेशे से अपनी और अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर है।

कालखण्ड गवाह है कि वेश्यावृत्ति हर काल में अपने अस्तित्व को बनाये रखी है। जहाँ विशेष समारोह में अतिथियों को विशिष्टता का एहसास कराती उनकी उपस्थिति और प्रस्तुति, तो दूसरी ओर समाज का कलंक कह कर उनकी छाया को भी मुख्य धारा से कहीं दूर धकेलने की तथाकथित सभ्य सोच का दोहरापन भी एक सच्चाई है। आज आँकड़े गवाह है कि 3 मिलियन से ज्यादा महिलाएँ जिनमें 40 प्रतिशत बच्चियाँ है, इसी धंधे से जीवन-यापन कर रही है। इनके लिए यह कानून वाला कानून लंबित हो रहा है।

इसमें कानून.... के तहत सभी गैर वैवाहिक Sexual Activities करने वालों एवं Sex Workers को एक साथ मिलाकर देखा जा रहा है फिर आगे Sex Work एवं मानव व्यापार को एक साथ जोड़ दिया गया जो इनके साथ सरासर अन्याय है।

राम बाजार के सभी Sectors में

कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी रूप में मानव व्यापार बेखटके चलता है लेकिन सिर्फ Sex Sector में मानव खरीद फरोक्त को अपराध बताया जाना अन्य स्थानों पर मानव व्यापार को जायज ठहराने के समान है।

इस कानून की धारा 3 कहती है कि Sex Worker का कार्य क्षेत्र चाहे जो हो, घर का कमरा हो या बाहर का कोई स्थान, आपराधिक गतिविधियों का अड्डा माना जायेगा। इस कानून को क्या गुंडे, बदमाश, अवारा तत्वों को खुली छूट नहीं दे दी कि वो इन्हें असुरक्षित और बेघर करने की धमकी देकर अपनी पाश्विक मुरादे पूर कर सकें।

धारा 4 में लिखा है कि Sex Worker की कमाई पर निर्भर बालिग व्यक्तियों को अपराधी माना जायेगा और इसके लिये उन्हें दो वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपया दण्ड स्वरूप देने का प्रावधान है, तात्पर्य तो यही हुआ न कि इनके बच्चे बालिक होने से पूर्व अपनी रोजी रोटी का इन्तजाम कर लें वरना जेल जाने को तैयार हो जायें। कैसा कानून है ये जो पीड़ितों के बच्चों से भी सम्मानजनक पेशा अपनाकर गरिमापूर्ण जीवन-जीने का अधिकार ही

छीन ले रहा है। आगे संशोधित प्रारूप की धारा 5(c) में Sex Worker के ग्राहकों को ही दोषी मान लिया जायेगा। अभिशप्त जीवन जी रहे पीड़ितों को सहायता और रक्षा मुहैया कराने की जगह उनके पेट पर ही—जाने अनजाने लात मारने की व्यवस्था है। दुःख होता है कि हम इतने असंवेदनशील कैसे हो जाते हैं।

Sex Worker का समूह समाज से कटा हुआ समूह है। कारण गौर करें तो पता चलेगा कि दो जून का भोजन भी जहाँ विलासिता हो वहाँ घर चलाने के लिए बच्चियों को बेच देना, कहीं दहेज देने की

असमर्थता कही लोभी पति द्वारा पत्नी को दलाल के हवाले कर देना कोई बड़ी बात नहीं। कभी-कभी जबर विवाह, बाल विवाह, बाल हत्याएँ, यौन हिंसा, वैधव्य, अशिक्षा, व्यंजन और कभी-कभी अति महत्वाकांक्षा भी इस नर्क में धकेले जाने का कारण बनते हैं। सेक्स उद्योग को जड़ से मिटाने की बात तो अभी कल्पना से परे है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक भागीदारी भी आड़े आती है। समस्या की जड़ें गहरी और फैली हुई हैं तो समाधान की कुदाली भी गहरी मगर समझदारी से चलानी होगी।

मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इन्हें भी श्रमिक कानून के तहत मान्यता मिल जाने से कुछ राहत मिलेगी। वर्तमान पुर्नवास का तरीका इन्हें Suit नहीं करता इसके लिए हमें इनके बीच से लोगों के साथ मिल बैठकर तरीका खोजना होगा। शिक्षित करना, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा की पहचान कराना और कल छोड़वाना इतना आसान नहीं होगा। इन्हीं की सहायता से इनके प्रति संवेदनशील सोच के साथ धीमा मगर निरंतर प्रयास ही इन्हें हाशिये से मुख्य धारा की ओर लाये और तभी इस कलंक रूपी पेशे के समूल खात्मे हेतु जमीनी मार्ग प्रशस्त होगा। ■



नयनज्योति



नेत्र चिकित्सा केन्द्र एवं लेजरलेन्स

डॉ० शिलेन्द्र कुमार

M.B.B.S. (PMCH), D.O./DOMS (PMCH)

फेको सर्जन, ओकुलोप्लास्टिक सर्जन

Ex-R.M.O. - Netaji Eye Hospital

Purulia (W.B.)

Consultant - Rotary Eye Hospital

Purulia (W.B.)

Life Member : All India Ophthalmological Society

मिलने का समय

सुबह 9:00 से 1:00 बजे तक

शाम 4:00 से 7:00 बजे तक

रविवार बन्द



9955227546, 9709938729

नोट : यहाँ आँख संबंधी सभी रोगों का आधुनिक मशीनों द्वारा जाँच कर ईलाज किया जाता है।

क्लिनिक का पता : पुरानी पी.एन.बी. गली, महावीर चौक से पश्चिम, होटल चित्रलेखा के बगल गली में, बनगाँव रोड (सहरसा)

स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाएँ

पटना (एसएनबी)। “ आप पश्चिम का अनुसरण न करें। इस बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा था और उन्होंने चेताया था कि इससे आपका मूल प्रभावित होगा। स्वामी जी के वर्तमान भारत लेख में इन सब बातों का जिक्र किया गया है।’ ये बातें न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह ने ‘स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत-भारतीय संविधान’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कहा।

न्यायमूर्ति ने कहा कि स्वामी जी की ‘वर्तमान भारत’ लेख के बारे में कहा गया था कि इसमें आधुनिक भारत के बारे में जिक्र है, लेकिन यह वर्तमान भारत के बारे में है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब इंग्लैंड ने राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो भारत पर शासन करने की बात सामने आयी। इसके लिए लार्ड मेकाले को भारत अध्ययन के लिए भेजा गया। उन्होंने यहाँ देखा कि गरीब और धनी के बीच काफी अंतर है। उनके इस अध्ययन के बाद विचार किया गया कि भारत के भारती की धरोहर को समाप्त किये जाने से उस पर शासन किया जा सकता है। इसी के तहत कई शैक्षणिक संस्थाएँ खोली गयीं। आज भारत की मूल शैक्षणिक संस्था समाप्त सी हो गयी है। इस तरह से उसने भारत में काफी बदलाव किया और इस देश की परंपरा से आ रही व्यवस्था समाप्त कर दी। न्यायमूर्ति ने कहा कि संविधान बनाये जानेसे पहले अंबेडकर के प्रस्ताव में स्वतंत्रता बरकरार रहने पर चिंता व्यक्त की गयी थी। उन्होंने विचार दिया था कि भारत में हजारों जातियाँ हैं और इस दशा में दुश्मन फिर से हावी हो जाएंगे और देश की स्वतंत्रता को समाप्त कर देंगे। आज भी जातियों के बीच इतना विद्वेष है कि वे भारत के विरुद्ध काम करते हैं।

संविधान दिवस-2013

With best compliments from :

M/s MAA TARA INDUSTRIES
SIKANDARPUR, BIHTA, PATNA



M/s BALA JEE ENTERPRISES
RUPASPUR, DANAPUR, PATNA

Vijay Kumar
(Proprietor)
9334131514

अधिवक्ता दिवस डा० राजेन्द्र प्रसाद की जयंती



न्यूज़ इनबॉक्स 24/11/2014 03/11/2014

न्यायिक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया

पटना | देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रख्यात अधिवक्ता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उनकी जयंती के अवसर पर पटना के अधिवक्ताओं ने याद किया। राजधानी के फ्रेजर रोड स्थित विश्व संवाद केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उच्च न्यायालय और जिला कोर्ट के अधिवक्ता जुटे। अधिवक्ता परिषद बिहार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में रवींद्र कुमार सिन्हा, सुनील कुमार, मुकुंद प्रसाद सिन्हा, शिखा परमार, हिमाचल राय, दिनेश कुमार सिन्हा एवं अनुराधा समेत कई अधिवक्ताओं ने सक्रियता से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। परिचर्चा में न्यायिक भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। अधिवक्ताओं के पंजीकरण के नवीकरण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा हाल में घोषित 500 रुपए पंचवर्षीय शुल्क का सभी अधिवक्ताओं ने एकमत से विरोध किया।

With best compliments from :

Er. Ram Balak Prasad

M.Tech (IIT Delhi), FIE, LIISA, FICA, FIV
Chartered Engineer & Valuer

SOCIAL ACTIVITY :-

धर्म जागरण समन्वय विभाग— अखिल भारतीय केन्द्रीय टोली सदस्य
भारतीय गोवंश रक्षण सम्वर्धन परिषद— द० बिहार संगठन मंत्री
संस्कार भारती — आजीवन सदस्य
उपाध्यक्ष — हरिहरनाथ — मुक्तिनाथ सांस्कृतिक यात्रा समिति, बिहार
उपाध्यक्ष— सरस्वती विद्या मंदिर, उत्तरी शास्त्रीनगर, पटना, बिहार

Valuer (Govt. Regd. & Approved)— (for Income Tax, Banks & Financial Institutions), Empanelled with Patna High Court, DRT, all nationalized banks for credit and recovery, surveyor & Loss Assessor, Arbitrator-empanelled by Indian council of Arbitration, GOI, Chairman-Institution of valuers, (Bihar & Jharkhand Charter)

Office :- 104, R.P. Tower (Near Jagat Trade Centre), Fraser Road, Patna-1 (Bihar)
E-mail :- rambalakprasad@sify.com, Phone - 0612-2285907, Mob. - 9835038711, 9431433109



Birendra Mohan Thakur
Secretary
B.M.T. Law College

B.M.T. LAW COLLEGE (AUTONOMOUS)

KAMLA BHAWAN, PURNIA, BIHAR

Contact No. - 09334317415, 06454-244487

Email : bmtlcautonomous@gmail.com Website : www.bmtlawcollege.org



[A Permanent Affiliated Unit of B.N. Mandal University, Madhepura, Autonomous Status granted by U.G.C, New Delhi Vide F. No. 22-1/June 2009 (AC), Permanently Recognized by the Bar Council of India, New Delhi]

THE ONLY AUTONOMOUS and NAAC ACCREDITED LAW COLLEGE IN BIHAR

AMBEDKAR AND VIVEKANAND STUDY CENTRE ESTABLISHED UNDER EPOCH SCHEME OF UGC IN THE CURRENT SESSION

- LL.M-2 Year Semester Course
- LL.B-3 Year Semester Course &
- B.A. LL.B (Hon's) 5 Year Double Degree Integrated Course

ESTABLISHED THE BENCHMARK IN QUALITY
EDUCATION IN LEGAL FIELD SINCE 1982